सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 352, नई दिल्ली । शुक्रवार, 28 फ़रवरी 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

सत्य बोलकर मित्र बनाना अच्छा है, परन्तु झूठ बेलकर मित्र बनाने से सत्य बोलकर शत्रु बनाना अधिक अच्छा है, क्योंकि आप संसार में सबको एक साथ प्रसन्न नहीं कर सकते।

03 कोई भी व्यवस्था, कानून और न्याय को कुचलकर स्थिर नहीं रह सकती
06 अधिसंख्य आबादी तक पहुंचें सस्ती दवाइयां
08 अमेरिका फर्स्ट या धन फर्स्ट?

परिवहन आयुक्त द्वारा दिल्ली की जनता के वाहन उठवाने के लिए नियुक्त वाहन स्क्रैप डीलरों द्वारा प्रयोग हो रहे बॉक्सर

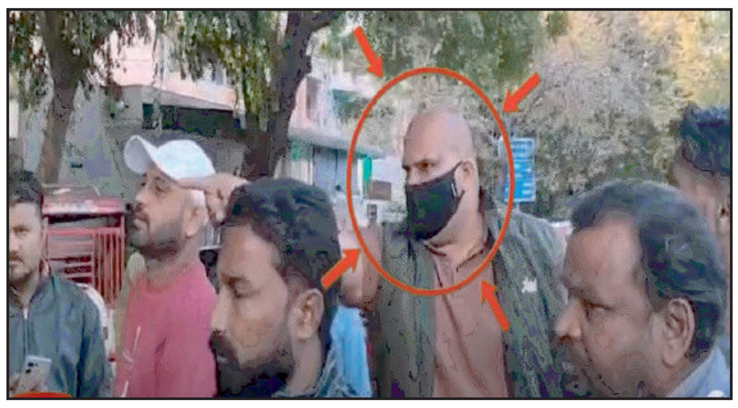

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार शिकायतें और वीडियो के माध्यम से सामने आ रहा हैं की वाहन स्क्रैप डीलरो के साथ प्रवर्तन शाखा का अधिकारी हो या नहीं हो पर गुंडागर्दी कर वाहन छीनने के लिए बॉक्सर / आपराधिक गतिविधियों के व्यक्ति होते हैं और हाथापाई करके वाहन छीन लेते हैं और

1. ई रिक्शा से बैटरी निकाल कर स्कूटर/ मोटरसाइकिल पर लेकर भाग जाते है।

2. विश्वस्त सूत्रों की जानकारी के अनुसार यह बात भी सामने आई है की इन स्क्रैप डीलरो ने ना तो वाहन मालिकों को पैसा दिया और ना ही पैसा परिवहन विभाग में जमा करवाया

3. विश्वस्त सूत्रों की जानकारी के अनुसार यह भी स्पष्ट हुआ है की ई रिक्शा की बैटरियां मार्केट में उस दाम पर बेच रहे है जितना पूरे ई रिक्शा के नाम पर भी नहीं देते

4. वाहन स्क्रैप डीलरो द्वारा वाहन स्क्रैप भी किए जा रहे हैं या ग्रे मार्किट (मायापुरी) की तरह वाहनों के पुर्जे या पूरा वाहन ही बेचा जा रहा है की भी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवाई जा रही

अब प्रश्न यह उठता है की **सब कुछ जानते हुए भी अपने प्रिय बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलरो के खिलाफ परिवहन आयुक्त कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे** और उससे भी बड़ा सवाल **जनता के साथ गैर कानूनी तरीके से कार्य करवाने वाले आईएएस अधिकारी के खिलाफ दिल्ली सरकार, मुख्य सचिव और उपराज्यपाल क्यों जांच के आदेश जारी नहीं कर रहे ?**

दिल्ली एयरपोर्ट : 5 महीने के लिए होंगे बंद टर्मिनल दो और एक रनवे

परिवहन विशेष न्यूज

आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 और एक रनवे को सुविधाओं के विस्तार और मजबूती के लिए 5 महीने के लिए बंद किया जाएगा। टर्मिनल 2 का ढांचा पुराना है और इसे अपग्रेड करने की जरूरत है। इस दौरान सभी उड़ानें टर्मिनल 1 से संचालित होंगी। टर्मिनल 3 के विस्तार की भी योजना है क्योंकि इसकी यात्री क्षमता से अधिक दबाव है।

नई दिल्ली। सुविधाओं को मजबूती और विस्तार देने के लिए आईजीआई एयरपोर्ट (IGI Airport) का टर्मिनल दो व एक रनवे करीब पांच महीने के लिए बंद किया जाएगा। एयरपोर्ट संचालन से जुड़ी एजेंसी डायल के अनुसार, दोनों को अप्रैल से बंद किया जाएगा। साथ ही एयरपोर्ट के टर्मिनल तीन के विस्तार की भी योजना तैयार की जा रही है।

काफी पुराना है टर्मिनल दो का ढांचा

डायल का कहना है कि टर्मिनल दो का ढांचा काफी पुराना है और इसे मजबूत किए जाने के साथ ही यहां के पूरे सिस्टम को अपग्रेड किए जाने की जरूरत है। इस पूरे कार्य में करीब पांच महीने का समय लगेगा। इसकी क्षमता करीब 15 मिलियन यात्रियों की है। जब यह बंद रहेगा, इस अवधि में यहां से संचालित होने वाली सभी उड़ानें टर्मिनल एक पर स्थानांतरित की जाएंगी।

क्षमता से अधिक यात्रियों का दबाव

बताया गया कि टर्मिनल तीन पर अभी क्षमता से अधिक यात्रियों का दबाव है। इसकी कुल यात्री क्षमता करीब 34 मिलियन यात्रियों की है, जबकि करीब 45 मिलियन यात्रियों को यहां संभाला जा रहा है।

योजना पर चल रहा है विचार

वहीं, इस दबाव को कम करने के लिए टर्मिनल तीन का विस्तार (खासकर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए) करने की योजना पर विचार चल रहा है। अभी टर्मिनल तीन पर सलाना 20 मिलियन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की क्षमता है, जबकि यहां अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का फुटफाल करीब 24 मिलियन के आसपास रहता है। यानि क्षमता से करीब 20 प्रतिशत यात्रियों की आवाजाही हो रही है। इसलिए टर्मिनल तीन के विस्तार की योजना पर कार्य हो रहा है।

अब ज्यादा देर तक दिल्ली की सड़कों पर नहीं रहेंगी खराब बसें
ट्रैफिक जाम का चांस कम, क्या है डीटीसी और पुलिस का प्लान ?

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में हर दिन करीब 400–450 बसें खराब होने से ट्रैफिक जाम हो जाता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और डीटीसी ने वाट्सऐप ग्रुप बनाया है। अब बस खराब होने पर नजदीकी डिपो का मैकेनिक उसे जल्दी ठीक करता है, जिससे जाम की स्थिति में सुधार हुआ है।

- दिल्ली में रोजाना 400–450 बसें ब्रेक डाउन होती हैं
- ट्रैफिक पुलिस और डीटीसी ने बनाया ब्रेक डाउन ग्रुप
- बस खराबी की सूचना वाट्सऐप ग्रुप पर तुरंत

नई दिल्ली: बस का ब्रेक डाउन होने या बस में कुछ खराबी आने की वजह से लोगों को कई बार बीच सड़क पर बस से उतरना पड़ता है। ब्रेक डाउन होने के बाद बस भी उसी जगह खड़ी रहती है। बस तब तक नहीं हटती है, जब तक इसे ठीक नहीं किया जाता। इस कारण सड़क पर लंबा जाम लग जाता है और लोगों को चंद समय का रास्ता तय करने में काफी समय लग जाता है।

स्पेशल कमिश्नर (ट्रैफिक) अजय चौधरी ने बताया कि दिल्ली परिवहन में करीब 10 हजार बसें हैं। दिल्ली में हर दिन करीब 400 से 450 बसों का ब्रेक डाउन होता है। इन बसों पर प्रेशर होता है। ऐसे में इन्हें धक्का देकर नहीं हटाया जा सकता है। मैकेनिक द्वारा ठीक करने के बाद ही बस को हटाया जा सकता है। इससे कई बार जाम की समस्या हो जाती है।

उन्होंने बताया कि इस समस्या को दूर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने डीटीसी के साथ मिलकर ब्रेक डाउन ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में ट्रैफिक पुलिस और डीटीसी के स्टाफ को जोड़ा गया है, ताकि अगर किसी बस का ब्रेक डाउन हो जाए तो तुरंत उसकी सूचना ग्रुप पर दी जाए और जल्द से जल्द बस को ठीक कर वहां से हटा दिया जाए ताकि जाम वाली नौबत न आए।

उन्होंने बताया कि पहले यह नियम था कि जिस डिपो की बस खराब हुई है तो उसे ठीक करने के लिए उसी डिपो से मैकेनिक आएगा। अगर उत्तम नगर बस डिपो की बस आनंद विहार जा रही है और वह रास्ते में खराब हो जाए तो उत्तम नगर डिपो का ही मैकेनिक उसे ठीक करने आएगा। इससे काफी परेशानी होती थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए यह नियम बनाया गया कि बस खराब होने पर नजदीकी डिपो के मैकेनिक आकर उसे तुरंत ठीक करेंगे।

वट्सऐप ग्रुप से सुलझ गई समस्या

स्पेशल कमिश्नर अजय चौधरी ने बताया इसके लिए ट्रैफिक पुलिस और डीटीसी का वट्सऐप ग्रुप बनाया गया है। अगर बस कही खराब होती है तो चंद सेकंड में डीटीसी का बस ड्राइवर, कंडक्टर या इलाके का टीआई उस बस का फोटो खींचता है और बस का नंबर और लोकेशन उस ग्रुप में डाल देता है। तब तुरंत नजदीकी डिपो वालों को यह सूचना मिल जाती है और वहां का मैकेनिक आकर जल्द से जल्द बस को ठीक कर देता है। उन्होंने बताया कि अगर बस खराब हो जाए और मैकेनिक को आने में समय लग जाए तो उससे भी निजात दिलाने के लिए बस ड्राइवर, कंडक्टर और ट्रैफिक पुलिस को समय-समय पर ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वह खुद भी खराब बस को ठीक कर सकें।

मात्र 30 मिनट में दिल्ली से जयपुर : भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक अब वास्तविकता बन चुका है!

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। आईआईटी मद्रास ने रेल मंत्रालय के सहयोग से 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया है, जिससे 350 किलोमीटर की दूरी महज 30 मिनट में तय की जा सकेगी। भविष्य में आप दिल्ली से जयपुर तक की लगभग 300 किलोमीटर की दूरी आधे घंटे से भी कम समय में तय कर सकेंगे। यह परियोजना, जिसे 'अविष्कार हाइपरलूप' नाम दिया गया है, आईआईटी मद्रास परिसर में बनाई गई है।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की जानकारी साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "सरकार और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग भविष्य के परिवहन क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दे रहा है।" इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 422 मीटर का यह पहला पॉड तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

हाइपरलूप एक मिलियन डॉलर का तीसरा अनुदान- परियोजना के परिणामों से उत्साहित होकर वैष्णव ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि समय आ गया है जब पहले दो अनुदानों के बाद, एक-एक मिलियन डॉलर का तीसरा अनुदान आईआईटी मद्रास को हाइपरलूप परियोजना को आगे विकसित करने के लिए दिया जाएगा।" उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे जल्द ही पहली वाणिज्यिक परियोजना शुरू करने की योजना भी बना रही है।

हाइपरलूप ट्रैक क्या है ? हाइपरलूप, जिसे "परिवहन का पांचवां माध्यम" कहा जाता है, लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक उच्च गति वाली परिवहन प्रणाली है। इस तकनीक के माध्यम से ट्रेन विशेष कैप्सूल में वैक्यूम ट्यूब के अंदर बहुत अधिक गति से यात्रा कर सकती हैं। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "इसमें वैक्यूम ट्यूब के भीतर विद्युतचुंबकीय रूप से उड़ने वाला पॉड शामिल है, जो घर्षण और वायु प्रतिरोध को समाप्त करता है और संभावित रूप से पॉड को मैक 1.0 तक की गति प्राप्त करने की अनुमति देता है"। समुद्र तल पर मानक दिन में एक मैक लगभग 1,225 किलोमीटर प्रति घंटे (761 मील प्रति घंटे) की गति होती है।

मौसम से प्रभावित नहीं होगा हाइपरलूप- विज्ञप्ति में यह भी बताया गया है कि "हाइपरलूप की विशेषता होगी कि यह मौसम से प्रभावित नहीं होगा, टकराव-मुक्त यात्रा प्रदान करेगा जो हवाई जहाज की गति से दोगुनी गति से चल सकता है, कम बिजली की खपत के साथ और 24 घंटे के संचालन के लिए ऊर्जा भंडारण की क्षमता रखेगा।"

हाइपरलूप भारत के परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव- हाइपरलूप तकनीक भारत के परिवहन क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। इस तकनीक के व्यावहारिक उपयोग के साथ, लंबी दूरी की यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, जिससे लोगों की यात्रा अनुभव में सुधार होगा और समय की बचत होगी। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं का मानना है कि हाइपरलूप तकनीक भारत के परिवहन ढांचे को बदल सकती है। यह न केवल यात्रा के समय को कम करेगी, बल्कि यह पर्यावरण के अनुकूल भी है क्योंकि इसमें कम ऊर्जा की खपत होती है।

चुनिंदा देशों में शामिल- हाइपरलूप परियोजना की सफलता से भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा, जो इस अत्याधुनिक तकनीक का विकास कर रहे हैं। यह न केवल देश के परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा देगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइपरलूप तकनीक का उपयोग मालवाहक परिवहन के लिए भी किया जा सकता है, जिससे देश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इससे उत्पादों की डिलीवरी तेजी से होगी और लागत में भी कमी आएगी।

तकनीकी चुनौतियां और समाधान- हालांकि हाइपरलूप तकनीक अत्यंत आशाजनक है, लेकिन इसके व्यावहारिक कार्यान्वयन में कई चुनौतियां हैं। इनमें निर्माण लागत, सुरक्षा मानक और नियामक अनुमोदन शामिल हैं। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ता इन चुनौतियों पर काम कर रहे हैं और इन्हें हल करने के लिए नवीन समाधान खोज रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत की जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, हाइपरलूप जैसी तकनीक का विकास देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह बड़े शहरों के बीच यात्रा के समय को कम करके देश के विकास को गति प्रदान करेगा।

सामान्य जनता के लिए लाभ- आम लोगों के लिए हाइपरलूप तकनीक कई फायदे लेकर आएगी। तेज़ और सुरक्षित यात्रा के अलावा, यह यात्रा का समय भी काफी कम कर देगी। इससे लोग अपने घरों से दूर काम कर सकेंगे और रोजाना लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उनकी कार्य-जीवन संतुलन में सुधार होगा। इसके अलावा, हाइपरलूप तकनीक से पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। लोग कम समय में अधिक स्थानों की यात्रा कर सकेंगे, जिससे देश के पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि होगी।

सरकार-अकादमिक सहयोग का महत्व- इस परियोजना की सफलता सरकार और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस तरह के सहयोग से न केवल नवाचार को बढ़ावा मिलता है, बल्कि देश के युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिलता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार भविष्य के तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह की परियोजनाओं को समर्थन देना जारी रखेगी।

कार्यों की सिद्धि के लिए होते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग

ज्योतिषाचार्य पंडित योगेश पौराणिक (इंजी.)

हिंदू पञ्चांग के अनुसार किसी भी वार में विशेष नक्षत्र पड़ने से सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। यह कभी कभी विवाह को छोड़कर बाकी अन्य सभी कार्यों में सफलता प्राप्ति हेतु त्वरित मुहूर्त का काम करता है। सर्वार्थ सिद्धि योग में सभी प्रकार की खरीदारी, शेयर बाजार में निवेश, खाता खुलवाना, वस्त्र सिलवाना, नई नौकरी या नया व्यापार शुरू करना, शिक्षा ग्रहण करना इत्यादि किया जा सकता है

प्रत्येक वार में पड़ने वाले नक्षत्रों से बनने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग निम्नलिखित प्रकार से है।

1) रविवार – अश्वनी, हस्त, पुष्य, तीनो उतरा एवं मूला
2) सोमवार – श्रवण, अनुराधा, रोहिणी, पुष्य, मृगशिरा
3) मंगलवार – अश्वनी, कृतिका, आश्लेषा, उतराभाद्रपद
4) बुधवार – कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा
5) गुरूवार – अश्वनी, पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा, रेवती
6) शुक्रवार – अश्वनी, पुनर्वसु, अनुराधा, श्रवण, रेवती
7) शनिवार – रोहिणी, स्वाति, श्रवण

दीर्घ एवं निरोगी जीवन के नियम

1. प्रातः ब्राह्ममुहूर्त में उठें। सुबह-शाम खुली हवा में टहलें, दौड़ें।

2. प्राणायाम, ध्यान, जप, योगासन, संयम-सदाचार आदि का नियम बना ले।

3. दिन में २- बार 'देव- मानव हास्य प्रयोग' करें।

4. कसे हुए, चटकीले-भड़कीले, गहरे रंग के, तंग व कृत्रिम (synthetic) कपड़े न पहनें। ढीले-ढाले सूती वस्त्र या ऋतु- अनुसार ऊनी वस्त्र पहनें।

5. संयम से रहें। ऋतुचर्या के अनुसार आहार-विहार करें।

6. पेशाब करने के तुरंत बाद पानी न पियें, न ही पानी पीने के तुरंत बाद पेशाब हेतु जायें। इससे हानि होती हैं। मल-मूत्र का वेग नहीं रोकें।

7. सप्ताह में कम-से-कम एक दिन रोज के संसारी कार्यों से मुक्त हो जायें। सप्ताह में कम-से-कम एक दिन थोड़ा हलका आहार लेकर घर के पूजा-कक्ष में मौन रह के अधिकांश समय सत्संग-श्रवण, श्री योगवासिष्ठ महारामायण ग्रंथ व आश्रम से प्रकाशित अन्य सत्साहित्य का स्वाध्याय, ध्यान, जप, अजपाजप, साक्षीभाव का अभ्यास आदि साधनों का विशेषरूप से लाभ लें।

8. स्वास्थ्य-मंत्र 'ॐ हंसं हंसः' का नित्य १०८ बार (एक माला) जप करें।

9. ब्रह्मवेत्ता संत-सद्गुरु के सत्संग का नियमितरूप से लाभ लें व दूसरों को भी दिलायें।

10. चाय-कॉफी, शराब-कबाब, धूम्रपान पान-मसाला सेवन, फिल्मी गाने सुनना, अश्लील दृश्य व चलचित्र तथा गंदी वेबसाइट्स देखना आदि किसी भी हानिकारक चीज की लत लगी हो तो उसे छोड़ने का व्रत लें व उस व्रत पर दृढ रहें।

11. रात को सोते समय यह प्रयोग करें : भगवन्नाम का उच्चारण करो और भगवान से कह दो कि 'हम जैसे-तैसे हैं, तेरे हैं। ॐ शांति... ॐ 'शांति... ॐ आनंद...' ऐसा करके लेट गये और श्वास अंदर जाय तो 'ॐ', बाहर आये तो '१'... श्वास अंदर जाय तो 'शांति', बाहर आये तो '२'... श्वास अंदर जाय तो 'आरोग्य', बाहर आये तो ' '... इस प्रकार श्वासोच्छ्वास की गिनती करते-करते सोयें। इससे स्वास्थ्य-लाभ तो मिलेगा ही, साथ-ही-साथ रात्रि की निद्रा कुछ सप्ताह में योगनिद्रा बनने लगेगी और आप परमात्मा में पहुँच जाओगे।

अदरक की चाय कुदरती रूप से माइग्रेन दूर भगाये

अदरक की चाय कुदरती रूप से माइग्रेन दूर भगाये माइग्रेन का दर्द असहनीय होता है और इसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल खासकर सुबह के वक्त दर्द और तेज हो जाता है। माइग्रेन के कारण उल्टी और नौसा की समस्या हो सकती है। इस दर्द को दूर करने के लिए अदरक की चाय पियें। अदरक की चाय पीने से माइग्रेन का दर्द प्राकृतिक रूप से दूर होता है। सामान्यतया अस्वस्थ जीवनशैली और खानपान में पौष्टिक तत्वों के अभाव के कारण तनाव और सिरदर्द की समस्या आम होती जा रही है। तनाव और सिरदर्द अधिक दिनों तक रहे तो यह माइग्रेन का रूप ले लेता है। माइग्रेन का दर्द कुछ घंटे से लेकर कई दिनों तक रह सकता है। इस लेख में विस्तार से जानिये कैसे अदरक की चाय प्राकृतिक रूप से माइग्रेन को दूर करने में मददगार है। क्या है माइग्रेन पहले माना जाता था कि माइग्रेन मस्तिष्क की रक्त नलिकाओं के फैलने और सिकुड़ने के कारण होता है, लेकिन कई अनुसंधानों में यह बात सामने आई है कि माइग्रेन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी के कारण होता है, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर्स का संचरण प्रभावित होता है, विशेष रूप से सेरोटोनिन हार्मोन में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और यह माइग्रेन बन जाता है। माइग्रेन के दो प्रकार होते हैं - क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। जब माइग्रेन का दर्द ऑरा यानी दृष्टि संबंधी गड़बड़ी के बाद शुरू होता है, तब इसे क्लासिकल माइग्रेन कहते हैं। इसमें आमतौर पर सिरदर्द के 10-15 मिनट पहले ऑरा के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब सिरदर्द बिना 'ऑरा' और दूसरे लक्षणों के साथ शुरू होता है, तब इसे नॉन क्लासिकल या सामान्य माइग्रेन कहते हैं। सामान्य माइग्रेन बच्चों और किशोरों में अधिक होता है। माइग्रेन के जो कुल मामले देखे जाते हैं, उनमें से 70 से 85 प्रतिशत सामान्य माइग्रेन और 15 से 30 प्रतिशत क्लासिकल माइग्रेन वाले होते हैं। छोटे बच्चों में माइग्रेन के दौरे शाम को पड़ते हैं। अदरक की चाय है फायदेमंद माइग्रेन के दर्द पर काबू पाने के लिए अदरक की चया का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है। अदरक एक बेहतरीन नैचुरल पेनकिलर है। अदरक में एंटी-इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो किसी भी प्रकार के दर्द पर आसानी से काबू पा लेते हैं। यानी अगर आपको सिरदर्द, तनाव, माइग्रेन की समस्या हो तो उसे दूर करने के लिए अदरक की चाय का सेवन कीजिए। इसके अलावा अदरक में ऐसे तत्व भी पाये जाते हैं जो पाचन क्रिया को सुचारु करते हैं। यानी माइग्रेन के कारण होने वाली मतली और उल्टी की शिकायत भी दूर होती है। कैसे करें प्रयोग अदरक की चाय बनाने के लिए अदरक का एक छोटा टकड़ा लेकर उसे अच्छे से छील लीजिए। फिर उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, उबलते पानी में इन टुकड़ों को डाल लीजिए। फिर इसे 10-15 मिनट तक उबालिये। उसके बाद इसे छानकर पीजिए। इसमें चीनी या शुगर की बजाय इसका अधिक फायदा उठाने के लिए शहद या नींबू का रस मिलायें।

फैटी लीवर का प्रोसेस

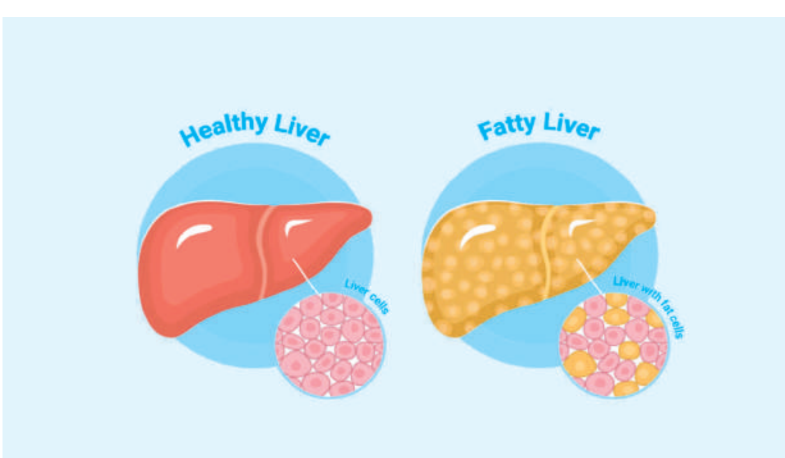

बाहर का अपशिष्ट खाना खाने, ऑइली स्पाइसी फ्राइड खाने, मांस और शराब का सेवन करने से लीवर के बाहर और अंदर फैट जमा हो जाती है जिसके कारण वह प्रॉपर रूप से काम नहीं करता। फैटी सैल्स होने के कारण लिवर इंसुलिन को ऑब्जर्व नहीं कर पाता जिसके कारण शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने लग जाती है। लीवर का डाइजेशन प्रोसेस कम हो जाता है जिसके कारण यह शरीर में गैस बनने लग जाता है और फैट हमारे रक्त वाहिनियों में जमा होने लग जाती है जो की कोलेस्ट्रोल का रूप लेती हैं। धीरे-धीरे फैट इतना बढ़ जाता है कि ब्लड का सरकुलेशन कम हो जाता है जिसके कारण हाई बीपी की शिकायत हो जाती हैं और लगातार हाई बीपी रहने से किडनी पर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। एक तरफ से शुगर और दूसरी तरफ से हाई बीपी होने के कारण किडनी आफ्टर होने लग जाती हैं। व्यक्ति डायलिसिस पर चला जाता है और प्रभु का सिमरन करने के अलावा कोई काम नहीं रहता। इस प्रकार की समस्याओं का इलाज आज भी आयुर्वेद में उपलब्ध है, परामर्श ले और स्वस्थ जीवन का लाभ उठाएं।

पेट में अल्सर (आमाशय/पक्वाशय में व्रण)

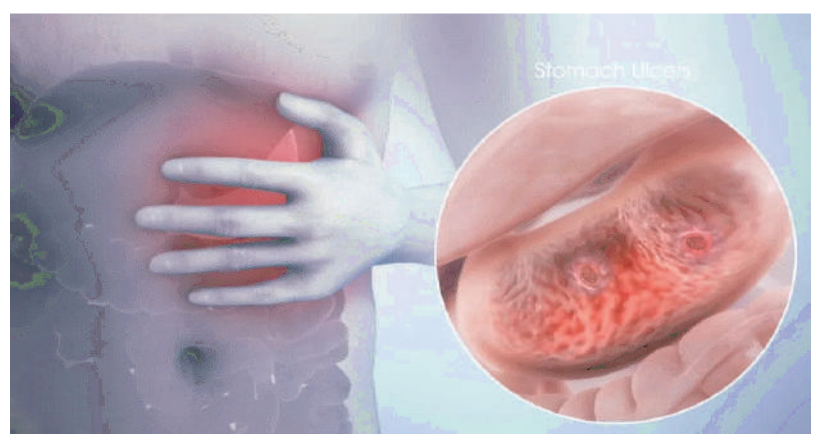

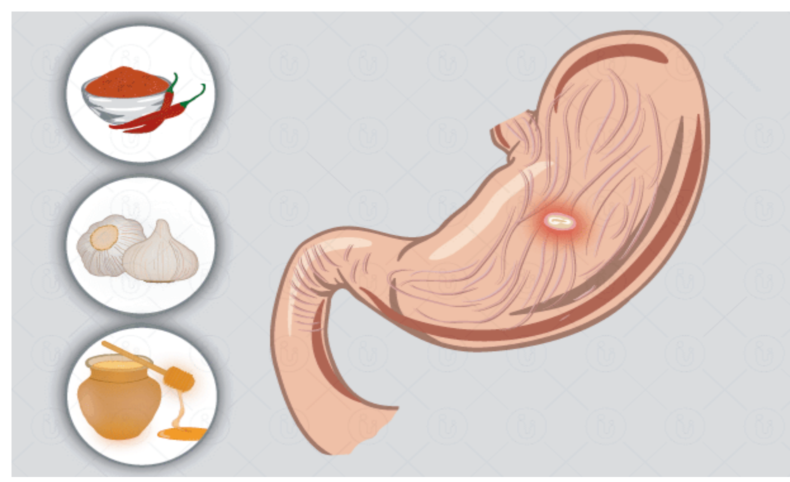

इस रोग में आमाशय में ऊपर, बीच में अथवा बिल्कुल नीचे के भाग में व्रण घाव या छाला अल्सर हो जाता है। इस रोग का मुख्य कारण ₹अम्लर₹ एसिड का अधिक बनना है। प्रायः शराब, माँस, मिर्च-मसाले, युक्त अधिक चटपटा भोजन, अधिक लाल मिर्चों का सेवन, अरहर, उड़द की दालें, अमचूर, खट्टे आम, खट्टे अंगूर, आम व नीबू का आचार, खट्टा दही व खट्टी चटनियाँ और खैनी (चूने में मिलाकर खायी जाने वाली तम्बाकू) के खाने से अम्ल/एसिड बनता है, जिसके फलस्वरूप ये ₹व्रणर₹ बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त चाय, कॉफी, पेप्सी, कोका कोला आदि कैफीन वाले पेय पदार्थ, कोलतार (पेट्रोलियम) युक्त पदार्थ औषयिाँ (जैसे ऐलोपैथीक की जुलाब की दवाइयाँ, नींद की गोलियाँ, सिन्थेटिक्स विटामिन्स तथा दर्द निवारक एसप्रिन आदि), सर्दी, जुकाम व दमा रोगों में प्रयुक्त की जाने वाली ऐलोपैथिक औषयिाँ, सन्धिवात/आमवात के रोगियों को लम्बे समय तक ऐलोपैथिक औषधियों के प्रयोग से तथा मदिरा पान करने वाले शौकीन व्यक्तियों के अतिरिक्त धूम्रपान, वनस्पति घी से निर्मित मिठाइयाँ तथा अन्य भोज्य पदार्थ आदि भी इस रोग को उत्पन्न करने में बहुत ही सहायक हैं। आजकल के नवीनतम् अनुसन्धानों में इसका एक कारण ₹मानसिकर₹ तनाव/चिन्ता (टेन्शन) भी माना जा रहा है। इस रोग से पीड़ित रोगी के पेट में हल्का-हल्का दर्द रहता है। यह दुर्द हल्के रूप में प्रारम्भ होता है, जो भोजन के आधा घण्टा बाद बहुत तीव्र तेज हो जाता है तथा कभी-कभी वमन द्वारा भोजन भी बाहर निकल जाता है। रोगी स्वयं भी वमन/कै करने का प्रयास करता है; क्योंकि वमन हो जाने के उपरान्त प्रायः रोगी का पेट दर्द शान्त हो जाता है।

कुछ सरल घरेलू आयुर्वेदिक प्रयोग

1. अविपत्तिकर चूर्ण 3 ग्राम, स्वर्ण माक्षिक भस्म 2 रत्ती. शौक्तिक भस्म 4 रत्ती (प्रत्येक शास्त्रोक्त औषधि बाजार में उपलब्ध है।) मिलाकर। मात्रा (पुड़िया बना लें या खाली कैपसूल में भर लें।) पुड़िया को दिन में 2 बार गुलकन्द या शहद के साथ अथवा कैपसूल को ताजा जल के साथ सेवन करें।

2. सफेद जीरा और धनिया समान मात्रा में लेकर, पीस कूटकर चूर्ण बनाकर शक्कर के साथ सेवन करें।

3. करेले के फूल या पत्तों को गाय के घी में भूनकर उनका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 1-2 ग्राम की मात्रा में दिन में 2-3 बार सेवन करें।

4. चिरायते के 2 ग्राम चूर्ण में भाग 4 रत्ती मिलाकर 100 मि०ली० जल में रात्रि के समय भिगो दें तथा प्रातः समय छानकर सेवन करें।

5. मुनक्का (दाख) 50 ग्राम और सौंफ 25 ग्राम लेकर यवकूट कर (मोटा-मोटा) दरदरा कूटकर। गिलास जल (200 मि०लि० जल) में रात्रि के समय भिगो दें और प्रातः समय मसल-छानकर उसमें 10 ग्राम मिश्री मिलाकर सेवन करें।

6. सवांग सुन्दर रस, मण्डूर भस्म, शंख भस्म और मुक्त शक्ति भस्म-प्रत्येक 125-125 कि०ग्रा०-ऐसी 1-1 मात्रा दिन में 3 बार मधु के साथ दें।

7. कुमार्यासव 20 मि०लि० समभाग जल मिलाकर भोजनोपरान्त दिन में 2 बार दें। सूतशेखर रस 250 मि०ग्रा०, कामदुधा रस व जहर मोहरा पिष्टी 125-125 ग्राम-ऐसी। मात्रा प्रातः समय दूध के अनुपान के साथ दें।

8. प्रवाल पिष्टी 250 मि०ग्रा०, अमृतासत्व व शूलवज्रिणी वटी-125-125 मि०ग्रा० ऐसी। मात्रा गाय के घी के साथ दिन में 3 बार रोगी को सेवन करायें। चन्दनादि वटी 500 मि०ग्रा० दिन में 2 बार सुबह - शाम जल के साथ रोगी को दें।

हड्डियों से चूस लेती है सारा कैल्शियम खाने से लेकर पीने वाली ये 5 चीजें, शरीर में छोड़ देते हैं बस चूरा ही चूरा

कैल्शियम हमारे शरीर के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत रखने के साथ-साथ हमारे रक्तचाप, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के सही संचालन में भी मदद करता है। यदि शरीर में कैल्शियम की कमी हो, तो हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जो शरीर से कैल्शियम को खत्म कर सकते हैं और हड्डियों को कमजोर बना सकते हैं? आइए जानते हैं, वो कौन से फूड्स हैं जिनसे आपको बचना चाहिए।

1. कोल्ड ड्रिंक (Soda) कोल्ड ड्रिंक, खासकर सॉफ्ट ड्रिंक्स, हर पार्टी या समारोह का हिस्सा बन जाते हैं। हालांकि, इन्हें ज्यादा मात्रा में पीने से शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। इन ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, जो शरीर से कैल्शियम के अवशोषण को रोकता है। इसके परिणामस्वरूप हड्डियों का कैल्शियम धीरे-धीरे कम होने लगता है। इसलिए अगर आप हड्डियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक का सेवन कम से कम करें।

2. रेड और प्रोसेस्ड मीट रेड मीट (जैसे मांसपेशी वाले मांस) और प्रोसेस्ड मीट (जैसे सॉसेज, बेकन, हॉट डॉग्स) का सेवन अत्यधिक करने से यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है, जो हड्डियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यह पदार्थ शरीर के भीतर कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं और हड्डियों को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए, अगर हड्डियों की सेहत का ख्याल रखना है, तो इन फूड्स का सेवन सीमित करना चाहिए।

3. केक, कैंडी और कुकीज केक, कैंडी और कुकीज जैसे मीठे और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में अत्यधिक शक्कर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कैल्शियम के अवशोषण में रुकावट डालते हैं। इसके अतिरिक्त, ये फूड्स शरीर में सूजन का कारण बन सकते हैं, जिससे हड्डियां और भी कमजोर हो सकती हैं। इसलिए, इन अत्यधिक मीठे पदार्थों को नियमित रूप से खाने से बचें और स्वस्थ स्नैक्स का चयन करें।

4. चाय (Tea) चाय में कैफीन पाया जाता है, जो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को कम करता है। अगर आप अधिक चाय पीते हैं, तो यह आपकी हड्डियों के लिए खतरनाक हो सकता है। विशेष रूप से अधिक कैफीन वाले चाय या कॉफी का सेवन हड्डियों से कैल्शियम को निकाल सकता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। इसलिए, चाय का सेवन सीमित करें और अधिक पानी या कैल्शियम से भरपूर अन्य पेय पदार्थों का सेवन करें।

5. शराब (Alcohol) शराब का अत्यधिक सेवन हड्डियों की सेहत पर गहरा असर डालता है। शराब शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को कम करती है और हड्डियों को कमजोर कर सकती है। यह हड्डियों को चूने के समान बना सकती है और हड्डी के फ्रैक्चर (हड्डी टूटने) का खतरा बढ़ा सकती है। अगर आप हड्डियों को मजबूत रखना चाहते हैं तो शराब का सेवन बहुत सीमित करें।

6. ऑयली फूड्स ऑयली फूड्स जैसे समोसा, फ्राइड चिकन, पकोड़ी, आदि हड्डियों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। ये अत्यधिक वसा और असंतुलित फैट्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर में सूजन पैदा कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, कैल्शियम का अवशोषण प्रभावित हो सकता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इन फूड्स को सीमित मात्रा में ही खाएं और स्वस्थ, हल्का भोजन करें।

कैल्शियम हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है और इसके सही अवशोषण के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अगर आप अपने हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो इन फूड्स का सेवन सीमित करें या पूरी तरह से बचें:

1. कोल्ड ड्रिंक
2. रेड और प्रोसेस्ड मीट
3. केक, कैंडी, कुकीज
4. ज्यादा चाय और कॉफी
5. अत्यधिक शराब
6. ऑयली और फ्राइड फूड्स

इसके बजाय कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल, नट्स और बीज आदि का सेवन करें। नियमित रूप से व्यायाम और हड्डियों को मजबूत करने वाली आदतों को अपनाने से भी आप अपनी हड्डियों को स्वस्थ रख सकते हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

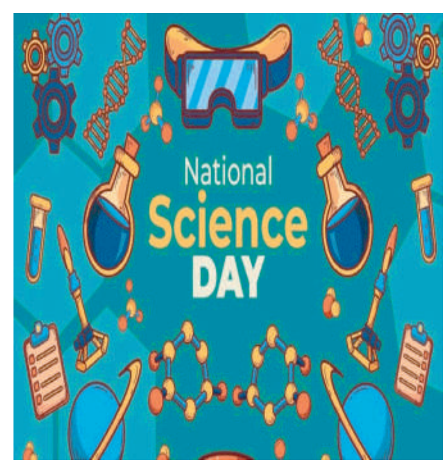

प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारतीयों के लिए एक विशेष उत्सव का प्रतीक है। यह उस दिन की वर्षगांठ है जब भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सी.वी. रमन ने एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज की थी। आज, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विज्ञान के महत्व को दर्शाता है और आम लोगों को यह देखने का अवसर देता है कि वैज्ञानिक नवाचार किस तरह से जीवन को बेहतर बना सकते हैं और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का इतिहास चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें आमतौर पर सी.वी. रमन के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिभाशाली बालक थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी, 11 साल की उम्र में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की और 13 साल की उम्र में अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी की, बाद में 16 साल की उम्र में उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। जबकि उन्होंने भौतिकी का अध्ययन किया था - सम्मान के साथ उत्तीर्ण हुए - उन्होंने लेखांकन को एक 'सुरक्षित विकल्प' के रूप में चुना, केवल तभी छोड़ दिया जब उन्हें अंततः 1917 में भारत में कलकत्ता (अब कोलकाता) के एक कॉलेज में पढ़ाने का पद दिया गया। चार साल बाद, यूरोप की यात्रा पर, रमन ने पहली बार हिमखंडों और भूमध्य सागर का नीला रंग देखा। वह समझ नहीं पाए कि यह रंग कैसे दिखाई देता है और उन्होंने उस समय के प्रचलित सिद्धांत को गलत साबित करने का प्रयास किया, जिसमें कहा गया था कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर सूर्य का प्रकाश बिखर जाता है, जिससे अलग-अलग रंग दिखाई देते हैं।

रमन ने खुद ही प्रयोग करना शुरू किया, बाद में अपने छात्र केएस कृष्णन को शोध की ज़िम्मेदारी सौंपी। उन्होंने पाया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से होकर गुजरता है, तो कुछ प्रकाश अलग-अलग दिशाओं में बिखर जाता है। 1928 में प्रकाशित इन परिणामों ने वैज्ञानिक समुदाय को इतना प्रभावित किया कि रमन को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें उसी वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उस वर्ष और अगले वर्ष उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि, रमन का अपनी खोज में विश्वास डगमगाया नहीं और उन्हें खुद पर इतना भरोसा था कि उन्होंने जुलाई में स्टॉकहोम जाने वाले स्टीमर पर दो टिकट बुक किए - एक अपने लिए और एक अपनी पत्नी के लिए - जब नवंबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होनी थी। उन्होंने उस वर्ष भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता, जिससे उनके काम और भारतीय वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान उनकी ओर गया।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कैसे मनाएं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उत्सव में कई गतिविधियाँ शामिल हैं जिनका उद्देश्य जागरूकता फैलाना और अधिक लोगों को वैज्ञानिक चर्चाओं में शामिल करना है।

1. स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान वर्तमान वैज्ञानिक विषयों पर वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, विज्ञान मेले और व्याख्यान आयोजित करते हैं।

2. सरकारी निकाय और अन्य वैज्ञानिक संस्थान भी नवीनतम वैज्ञानिक खोजों और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए सार्वजनिक प्रदर्शनियों का आयोजन करते हैं।

अदालत को पीएम मोदी की डिग्री दिखा सकते हैं, अजनबियों को नहीं: डीयू ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर दायर याचिका पर अपना पक्ष रखा है। डीयू ने कहा कि उसे पीएम की डिग्री अदालत को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वह इसे अजनबियों की जांच के दायरे में नहीं लाएगा। डीयू की तरफ से पेश हुए एसजी तुषार मेहता ने कहा कि एक छात्र की डिग्री की मांग की जा रही है जो देश के प्रधानमंत्री हैं।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ी याचिका पर बृहस्पतिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने कहा कि उसे पीएम की डिग्री अदालत को दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह इसे अजनबियों की जांच के दायरे में नहीं लाएगा। डीयू की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि एक छात्र की डिग्री की मांग की जा रही है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं।

एसजी ने कहा कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और बीए की मूल डिग्री को अदालत में दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन डीयू के रिकॉर्ड को उन लोगों के सामने उजागर नहीं करेंगे जो या तो प्रचार या किसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक उद्देश्य के लिए यहां आए हैं। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने एसजी का पक्ष सुनने के बाद मामले पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।

CIC के आदेश पर हाईकोर्ट ने 2017 में लगाई थी रोक

डीयू ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को चुनौती दी है। सीआईसी ने डीयू को सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत दिसंबर-2016 में आवेदनकर्ता नीरज शर्मा को 1978 में बीएस परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का आदेश दिया था। इसी वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पास की थी।

CIC के उक्त आदेश पर हाईकोर्ट ने 23 जनवरी 2017 में रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ता नीरज शर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएम की डिग्री का विवरण मांगा था। डीयू ने यह कहते हुए डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था कि यह निजी जानकारी है और इसका सार्वजनिक हित से कोई लेना-देना नहीं है।

सीआईसी द्वारा पारित आदेश हो रद- एसजी तुषार मेहता

गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने कहा कि जानने का अधिकार कोई अछूता अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पुट्टास्वामी मामले में एक निष्कर्ष सर्वसम्मति से पारित किया गया था कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। उन्होंने यह भी कहा कि आरटीआई अधिनियम के तहत व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी जा सकती।

एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हमारे पास यह है लेकिन हम इसे नहीं देंगे क्योंकि हम इसके लिए वैधानिक रूप से बाध्य नहीं हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आरटीआई अधिनियम का इस्तेमाल अधिकारियों को डराने-धमकाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

यदि ऐसे आवेदनों पर विचार किया जाता है तो सार्वजनिक अधिकारी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि आरटीआई अधिनियम का उपयोग अपनी ड्यूटी कर रहे अधिकारियों को डराने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है। एसजी तुषार मेहता से कहा कि सीआईसी द्वारा पारित आदेश को रद किया जाना चाहिए।

अमेरीकेयर्स इंडिया फाउंडेशन ने सफदरजंग अस्पताल को प्रदान की उन्नत फाइब्रोस्कैन मशीन

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नईदिल्ली। अमेरीकेयर्स इंडिया फाउंडेशन ने लीवर रोग प्रबंधन के लिए दैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल के तहत सफदरजंग अस्पताल को उन्नत फाइब्रोस्कैन मशीन प्रदान की है।

औपचारिक हैंडओवर समारोह अमेरीकेयर्स इंडिया फाउंडेशन के कार्यक्रम निदेशक डॉ. उल्हास वासवे और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संदीप बंसल सहित विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में सफदरजंग अस्पताल में आयोजित किया गया।

फाइब्रोस्कैन, लीवर फाइब्रोसिस और स्टेटोसिस का आकलन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक गैर-इनवेसिव तकनीक है, जो इनवेसिव बायोप्सी की आवश्यकता के बिना लीवर की स्थितियों का निदान और निगरानी करने की अस्पताल की क्षमता में काफी सुधार करेगी। इस योगदान से हर साल भारत के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक में इलाज कराने वाले हजारों रोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

समारोह के दौरान डॉ. उल्हास वासवे ने कहा, ₹यह योगदान पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।₹ ₹फाइब्रोस्कैन जैसे उन्नत नैदानिक उपकरणों तक पहुँच प्रदान करके, हमारा उद्देश्य यकृत रोगों का शीघ्र पता लगाना और बेहतर प्रबंधन करना है।₹ डॉ. संदीप बंसल ने योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, ₹यह तकनीक यकृत रोग निदान के लिए हमारे दृष्टिकोण को बदल देगी और हमारी चिकित्सा टीमों को रोगियों को अधिक सटीक, समय पर और गैर-आक्रामक देखभाल प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। हम उनके उदार समर्थन के लिए अमेरीकेयर्स इंडिया फाउंडेशन को धन्यवाद देते हैं।₹ अमेरीकेयर्स इंडिया फाउंडेशन और सफदरजंग अस्पताल के बीच साझेदारी गैर-लाभकारी संगठनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के बीच महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभावी सहयोग का उदाहरण है। हैंडओवर समारोह में सभी अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. प्रदीप देबता एचओडी बाल रोग विभाग, संकाय, सीएसआर समिति के सदस्य और अमेरीकेयर्स इंडिया फाउंडेशन के सदस्य शामिल हुए।

अमेरीकेयर्स इंडिया फाउंडेशन के बारे में:

अमेरीकेयर्स इंडिया फाउंडेशन गरीबी या आपदा से प्रभावित लोगों के जीवन को बचाने और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों और साझेदारियों के माध्यम से, फाउंडेशन पूरे भारत में वंचित समुदायों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा संसाधन उपलब्ध कराने के लिए काम करता है।

विधानसभा में आप पार्टी के विधायकों को पुलिस बैरिकेडिंग द्वारा बाहर ही रोक दिया गया

मुख्य संवाददाता सुषमा रानी

नई दिल्ली :आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को तीन दिन के लिए सदन की बैठक से निष्कासित किया गया है। इस सिलसिले में आतिशी नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपने विधायकों के साथ उनसे मिलने की इच्छा जताई है

आदरणीय राष्ट्रपति महोदया,

आपके संज्ञान में एक अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील विषय लाना चाहती हूँ, जो भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला है।

दिल्ली में भाजपा की सरकार ने दिल्ली सरकार के विभिन्न दफ्तरों से संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद-ए-आज़म भगत सिंह की तस्वीर हटा दी है। ये न केवल देश के वीर सपूतों का अपमान है बल्कि दलित, पिछड़े और वंचित समाज का भी अपमान है।

जब आम आदमी पार्टी ने विपक्ष के रूप में इस कदम का विरोध किया और इस गंभीर मुद्दे को सदन में उठाने का प्रयास किया, तो विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने

अलोकतांत्रिक रूप से आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को 25 फरवरी को तीन दिनों के लिए सदन की बैठकों से निष्कासित कर दिया।

आज 27 फरवरी को जब आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली विधानसभा जा रहे थे, तो दिल्ली पुलिस द्वारा भारी बैरिकेडिंग कर हमे विधानसभा के परिसर के बाहर ही रोक दिया गया।

जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को विधानसभा तक पहुंचने से रोका जाना लोकतंत्र की हत्या है। इस कारण विपक्ष के विधायकों को सड़क पर ही धरने पर बैठना पड़ा। यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि विपक्ष को विधानसभा परिसर में भी प्रवेश नहीं करने दिया गया। यह घटनाक्रम भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर एक काला धब्बा है।

अगर विपक्ष को इस तरह रोका जाएगा, तो जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों का होना जरूरी है, ताकि आम लोगों की आवाज़ सुनी जा सके। लेकिन अभी जो हो रहा है, वह विपक्ष को दबाने की कोशिश है, जिससे जनता की आवाज़ भी दब रही है।

इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का विधायक दल आपसे तत्काल मुलाकात करना चाहते हैं ताकि इस तानाशाही के खिलाफ उचित कदम उठाए जा सकें। यह सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र पर संकट का संकेत है।

हम उम्मीद करते है कि आप इस अति गंभीर मामले पर तत्काल संज्ञान लेने की कृपा करेंगी और आम आदमी पार्टी के विधायकों को आपसे मिलने के लिए कल दिनांक 28/02/2025 का कोई समय निर्धारित करने की कृपा करेंगी।

महाकुंभ में भक्त शिरोमणि यजमान पेरिका सुरेश द्वारा शिव पुराण, महाकुंभ महात्म, एवं रुद्राभिषेक का भव्य आयोजन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भक्त शिरोमणि पेरिका सुरेश प्रयागराज में 144 वर्ष बाद आयोजित दुर्लभ अलौकिक महाकुंभ में 45 दिनों तक आगंतुको की सेवा एवं भोजन के प्रबंध में निस्वार्थ भाव से लग रहे। महाकुंभ के समापन अवसर पर यजमान एवं आयोजनकर्ता के रूप में श्री सुरेश ने शिव पुराण कथा वाचन का आयोजन किया, जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य के मुख से भक्तजनों ने शिव पुराण कथा का रसपान किया। तदउपरांत दांडी परंपरा के वाहक एवं मत मछली बंदर अस्सी घाट वाराणसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी विमल देव महाराज ने महाकुंभ महात्म की कथा भक्त जनों को श्रवण कराया। श्री आनंद ब्रह्मचारी जी महाराज द्वारा रुद्राभिषेक पूजन किया गया। डॉक्टर अभिषेक सबील आचार्य द्वारा रूद्रम नमाकाम प्रस्तुत किया गया।इस अवसर पर दांडी स्वामी महाराज आनंद स्वामी जोशी जी भी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त 1008 महाकुंभ पीठाधीश्वर एवं 540 अखाड़ा के नागा संतो एवं 270 मठाधीश्वर ने भी इस भव्य भागवत आयोजन पर अपनी कृपा पूर्ण उपस्थित से सभी भक्तजनों को कृतार्थ किया। सनातन धर्म अनुरागी परिका सुरेश ने 10 हजार साधु संतों को कंबल वितरित किए वहीं महाकुंभ के दौरान प्रत्येक दिन 2000 भक्त जनों के भोजन की व्यवस्था की। श्री सुरेश ने अपने इस पूण्य कर्म से साधु संतों का कृपा पूर्ण आशीर्वाद लिया तथा सनातन के उत्थान के लिए अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी देकर सभी दिलों में यादगार बन गए।

कोई भी व्यवस्था, कानून और न्याय को कुचलकर स्थिर नहीं रह सकती – मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी

मुख्य संवाददाता

संभल। : जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी के नेतृत्व में जमीयत उलेमा गुजरात के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज संभल हादसे के शहीदों के परिवारों से मुलाकात की और उनके प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए प्रत्येक परिवार को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस पहल का उद्देश्य रमजान से पहले प्रभावित परिवारों की सहायता करना और उनके साथ खड़े होने का वास्तविक प्रदर्शन करना है।

प्रतिनिधिमंडल में जमीयत उलेमा गुजरात के उपाध्यक्ष मौलाना अब्दुल कुद्दूस पालनपुरी, मौलाना अबुल हसन सिवानी (पालनपुर), मौलाना नदीम अहमद बदरखा और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। इस अवसर पर जमीयत उलेमा संभल के अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद शाहिद, महासचिव मौलाना नदीम अख्तर कासमी और स्थानीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के विशेष निर्देश पर, घटना के कुछ ही दिनों बाद केंद्रीय कार्यालय की ओर से प्रत्येक शहीद के परिवार को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता पहले ही प्रदान की जा चुकी है। जमीयत निरंतर पीड़ितों के संपर्क में है और उनकी हरसंभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है।

इस मौके पर मौलाना अब्दुल कुद्दूस पालनपुरी ने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी की विशेष ध्यानाकर्षण के बाद जमीयत उलेमा गुजरात यहां अपने भाइयों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने आई है। हमने हमेशा ही पीड़ितों और

जरूरतमंदों के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया है और आगे भी अपने धार्मिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों को निभाते रहेंगे।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी ने कहा कि जमीयत शुरुआत से ही संभल हादसे के पीड़ितों के साथ खड़ी है। हमारी राहत गतिविधियों का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि शहीदों के परिवारों के साथ एकजुटता प्रकट करना और उनके दुख में सहभागी बनना है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी व्यवस्था, कानून और न्याय को कुचलकर स्थिर नहीं रह सकती। हम संभल हादसे के पीड़ितों के साथ हर हाल में खड़े रहेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे कि पीड़ितों को न्याय मिले और उनकी आवाज बुलंद हो।

एनएक्सटी कॉन्क्लेव 2025 सभी शासन, प्रौद्योगिकी और आर्थिक परिवर्तन के अगले दशक को आकार देने के लिए तैयार हैं

सुषमा रानी मुख्य संवाददाता

नईदिल्ली। दुनिया परिवर्तनकारी परिवर्तन की अवक्षेप में है, और उद्घाटन एनएक्सटी कॉन्क्लेव 2025 को शासन, प्रौद्योगिकी और आर्थिक परिवर्तन में प्रगति के अगले दशक को आकार देने के लिए तैयार है। 28 फरवरी और 1 मार्च, 2025 को भरत मंडपम, नई दिल्ली में होने वाली प्रतिष्ठित स्थल- जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले प्रतिष्ठित स्थल पर होने वाला है। वैश्विक चुनौतियों को दबाना और प्रभावपूर्ण समाधान चलाना। जैसा कि राष्ट्र जटिल आर्थिक परिदृश्य, तेजी से तकनीकी प्रगति, और स्थिरता की तात्कालिकता को नेविगेट करते हैं, एनएक्सटी कॉन्क्लेव 2025 कार्रवाई के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। नवाचार में तेजी लाने, वैश्विक नीति निर्धारण को प्रभावित करने और रणनीतिक सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए, एनएक्सटी उद्योगों, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के भविष्य को आकार देने में एक परिभाषित भूमिका निभाएगा।

आईटीवी फाउंडेशन के चेयरपर्सन और एनएक्सटी के संचालन समिति के अध्यक्ष डॉ। ऐश्वर्या पंडित शर्मा ने कहा, ₹सच्ची प्रगति को प्रभाव से मापा जाता है, न कि केवल इरादे। वैश्विक चुनौतियों का पैमाना आज बोल्ड सॉल्यूशंस की मांग करता है। एनएक्सटी को एक बल बनने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वास्तविक परिवर्तन के लिए, यह सुनिश्चित करना कि हर बातचीत उद्योगों को फिर से परिभाषित करने, नीतियों को बदलने और एक स्थायी वैश्विक पदचिह्न बनाने वाले समाधानों की ओर ले जाती है। "

वैश्विक प्रगति के लिए परिवर्तनकारी अध्याय

दुनिया प्रगति के एक नए युग में प्रवेश कर रही है, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, हरित ऊर्जा, अंतरिक्ष अन्वेषण, वित्त, स्वास्थ्य सेवा, और शासन में सफलताओं के साथ, जिस तरह से हम रहते हैं और काम करते हैं। एनएक्सटी कॉन्क्लेव 2025 दावोस के लिए भारत का जवाब होगा - विचारों का एक वार्षिक पावरहाउस जहां सरकारें, निगम, और दूरदर्शी नीतियों को आकार देने, सफलता के नवाचारों का अनावरण करने और भविष्य के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए अभिसरण करते हैं। वास्तविक दुनिया के प्रभाव के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में डिज़ाइन किया गया, एनएक्सटी में अनन्य बड़े पैमाने पर परियोजना उद्घाटन, विश्व-पहले अनुसंधान घोषणाओं, लाखों तक पहुंचने वाले उच्च-हिस्सेदारी बंद-दरवाजे चर्चा होगी।

उपस्थित लोग गेम-चेंजिंग उत्पाद डेब्यू, अग्रणी अनुसंधान प्रस्तुतियों और दुनिया भर में उद्योगों और सरकारों को प्रभावित करने के लिए निर्धारित नीति रूपरेखाओं को देखेंगे। अगली पीढ़ी के एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों के लाइव प्रदर्शन भविष्य में एक झलक पेश करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि यह वैश्विक नेताओं और निवेशकों के बीच व्यावहारिक बंद-दरवाजे चर्चा की सुविधा प्रदान करेगा, जो बड़े पैमाने पर आर्थिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय नीति समझौतों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। अनन्य लीडरशिप राउंडटेबल्स के साथ, एनएक्सटी टिकाऊ विकास, तकनीकी उन्नति और भू -राजनीतिक स्थिरता को चलाने वाली भागीदारी के लिए सबसे उज्ज्वल दिमागों को एक साथ लाएगा।

एनएक्सटी कॉन्क्लेव 2025 के मूल में परिवर्तनकारी वैश्विक मंच के लिए एक बोल्ड विजन है जहां नेता निर्णायक कार्रवाई करते हैं, न कि केवल विचारों का आदान -प्रदान करते हैं। एनएक्सटी के संस्थापक और संसद सदस्य (राज्यसभा) के संस्थापक कार्तिकेय शर्मा ने इस महत्वाकांक्षा को समझाया, उजागर किया, ₹दुनिया एक चौराहे पर है जहां नेतृत्व को कार्रवाई के बारे में होना चाहिए, न कि केवल बातचीत के लिए। एनएक्सटी को वास्तविक के लिए उत्प्रेरक बनने के लिए बनाया गया है। परिवर्तन - जहां सफलता के विचार ठोस समाधानों में बदल जाते हैं, नीतियां प्रगति करती हैं, और नवाचार वैश्विक प्रभाव को बढ़ाता है। यह उद्योगों को आकार देगा, शासन को प्रभावित करेगा, और परिवर्तन के एक नए युग के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा।"

एनएक्सटी कॉन्क्लेव 2025, वास्तव में, नवाचार, वैश्विक नीति प्रभाव और प्रभावशाली सहयोग के लिए एक लॉन्चपैड होगा। सम्मानित पर्यटन भागीदार - पर्यटन वित्त निगम और भारतीय अंतरिक्ष संघ और अमेरिकी यहूदी समिति जैसे संस्थागत भागीदारों द्वारा समर्थित, यह उद्योगों में विशेषज्ञता को एकजुट करता है। ग्रीन सर्कल और स्वस्तिक ग्रीन्स इसके रियल्टी पार्टनर हैं। हयात रीजेंसी (गुड़गांव) शीर्ष स्तरीय आतिथ्य सुनिश्चित करेगा, जबकि संडे गार्जियन फाउंडेशन अपने संस्थापक साथी के रूप में लंबा है। न्यूज़एक्स, मीडिया पार्टनर के रूप में, लाइव कवरेज प्रदान करेगा, जो वैश्विक दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि लाएगा।

आर्थिक, तकनीकी और भू -राजनीतिक परिदृश्य विकसित करने के बीच, एनएक्सटी कॉन्क्लेव 2025 एक शक्तिशाली मंच के रूप में उभरता है, जो दुनिया भर में परिवर्तनकारी परिवर्तन को चलाने के लिए नेताओं को एकजुट करता है।

चुनिंदा तरीके से मुस्लिम स्वामित्व वाले विश्वविद्यालयों को निशाना बनाना चिंताजनक: मलिक मोतसिम खान

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान ने भाजपा शासित राज्य सरकारों द्वारा मुस्लिम स्वामित्व वाले विश्वविद्यालयों को चुन कर निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है।

मीडिया को जारी एक बयान में उन्होंने कहा, "देश भर में भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को निशाना बनाकर की गई गिरफ्तारियों और कानूनी कार्रवाइयों की घटनाओं पर हमें गंभीर चिंता है। असम में यूएसटीएम के चांसलर महबूब-उल-हक की मध्य रात्रि में गिरफ्तारी से लेकर राजस्थान में मौलाना आजाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के उत्पीड़न, ग्लोकल विश्वविद्यालय की संपत्तियों की कुर्की और उत्तर प्रदेश में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर लगातार कार्रवाई, मुस्लिम स्वामित्व वाले उच्च शैक्षिक केंद्रों को चुनिंदा रूप से निशाना बनाने का एक पैटर्न प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुस्लिम नेतृत्व वाली शैक्षिक प्रगति को दबाने के लिए इन संस्थानों को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। यह मुद्दा तब और भी गंभीर है जब इन कार्रवाइयों के साथ-साथ राजनेताओं द्वारा इन संस्थानों को कट्टरपंथ के पूर्णतः झूठे और भ्रामक आख्यान के तहत रूढ़िवादी और कलंकित करने के नियमित प्रयास भी किए जाते हैं।"

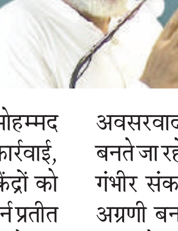

जमाअत के उपाध्यक्ष ने आगे कहा, "हमारा मानना है कि इस तरह की कार्रवाइयों से न केवल इन विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा धूमिल होती है, बल्कि अकादमिक उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत हजारों छात्रों और संकाय सदस्यों का भविष्य भी खतरे में पड़ता है। इन विश्वविद्यालयों को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक उपलब्धियों के बावजूद निशाना बनाया जाना देश में उनके शिक्षा और समान अवसर के मूल अधिकार के लिए खतरा है। जिस देश में वर्ग, जाति और पंथ की परवाह किए बिना सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है, वहां विश्वविद्यालयों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई एक संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है। यदि NAAC-मान्यता प्राप्त 'ए' ग्रेड विश्वविद्यालय राजनीतिक अवसरवाद और सांप्रदायिक पूर्वाग्रह का शिकार बनते जा रहे हैं, तो भारत में उच्च शिक्षा का भविष्य गंभीर संकट में है। शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनने तथा विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर खोलने के लिए आमंत्रित करने की हमारी कोशिश को गंभीर रुकावट तय है।हम मुस्लिम स्वामित्व वाले उच्च शिक्षा संस्थानों को इस तरह से निशाना बनाने की कार्रवाई को रोकने की मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकारें इस तरह की सांप्रदायिक और वोट बैंक की राजनीति करने से बचेंगी, क्योंकि इससे हजारों छात्रों के शैक्षिक हितों के लिए खतरा बन रहा है।"

प्राधिकरण के पास नहीं जमीन, हवा में बिल्डर बना रहे थे स्पोर्ट्स सिटी....

नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर किसानों से सस्ते दामों पर जमीन अधिग्रहित की गई और निवेशकों को गुमराह कर ठगा गया। प्राधिकरण के पास जमीन ही नहीं थी फिर भी बिल्डरों को सस्ती दरों पर जमीन दी गई। अब निवेशकों के फ्लैट कागजों में ही सिमट कर रह गए हैं। जानिए इस पूरे मामले का सच क्या है।

नोएडा। नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर जहां किसानों से सस्ते दाम पर जमीन अधिगृहीत की गई। वहीं, निवेशकों को भी गुमराह करके खूब ठगा गया है।

स्थिति यह है कि जिस जमीन पर फ्लैट बनाए जाने थे। उसमें से 15 खसरा नंबरों की 16.2512 हेक्टेयर भूमि जिला प्रशासन को 24 दिसंबर 2014 वापस कर दी गई थी। यानी प्राधिकरण के अफसरों और बिल्डरों के गठजोड़ से निवेशकों को उन फ्लैटों में निवेश करा दिया गया, जो कागजों सिर्फ कागजों में ही हैं।

प्राधिकरण ने तैयार की थी स्पोर्ट्स सिटी बनाने की कार्ययोजना

प्राधिकरण सीईओ डा. लोकेश एम ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस प्रकरण का विधि विभाग के साथ अध्ययन किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक स्पोर्ट्स सिटी आवंटन में बड़ा घोटला हुआ है। मात्र 10 प्रतिशत धनराशि पर सस्ती दर पर जमीन दी गई। आवंटन के बाद बिल्डरों ने नियम व शर्तों को पूरा नहीं किया। आवासीय व कामर्शियल स्पेश को मोटी दर पर बेच दिया गया। कामनवेल्थ गेम के दौरान 2008 में प्राधिकरण ने स्पोर्ट्स सिटी बनाने की कार्ययोजना तैयार की थी।

जमीन का क्षेत्रफल बढ़ व घट सकता है

इसमें सेक्टर-78, 79 व 101 आदि तीन सेक्टर स्पोर्ट्स सिटी के लिए आरक्षित किए गए। जनाडु इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड (कंसोटियम) को 7,27,500 वर्ग मीटर जमीन दी गई। 7,03,001.80 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा दे दिया गया। बाकी जमीन के लिए बिल्डर से कहा गया कि ब्रोशर शर्त के अनुसार जैसे बाकी जमीन उपलब्ध होगी, कब्जा दिया जाएगा। जमीन का क्षेत्रफल बढ़ व घट सकता है। कारण यह था कि प्राधिकरण के पास जमीन ही उपलब्ध नहीं थी।

बिल्डरों को सस्ती दरों में जमीन क्यों दी गई

किसान नरेश चंद्र यादव ने बताया कि सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्टर-101 की पूरी जमीन वापस कर दी। इससे यह सेक्टर स्पोर्ट्स सिटी से बाहर हो गया। सेक्टर-79 में भी सिर्फ 12.6788 हेक्टेयर जमीन बची थी। जबकि सेक्टर-78 में ग्रुप हाउसिंग व कामर्शियल भवन बन चुके हैं।

प्राधिकरण के पास जमीन ही नहीं थी तो स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर बिल्डरों को सस्ती दरों पर जमीन क्यों दी गई। अब बिल्डर से भूखंड की कीमत का बकाया नहीं मिलने का रोना रोया जा रहा है। जबकि बिल्डर जमीन नहीं मिलने की बात कहकर नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल में प्राधिकरण के खिलाफ गए है। इसकी आड़ में ब्याज माफी का भी लाभ लिया। बिल्डरों ने फ्लैट और दुकानों के लिए स्पेस बेच कर मोटी कमाई कर ली।

प्राधिकरण के पक्ष में पट्टा अनुबंध किया

किसान रवि यादव ने बताया कि प्राधिकरण ने किसानों की जमीन का अधिग्रहण तक नहीं किया। अधिकांश जमीन ग्राम सभा की थी। सेक्टर-79 के लिए बिना जमीन के ही कागजों में आवंटन कर दिया गया। जमीन लेने की प्रक्रिया प्रशासन ने तीन वर्ष बाद 2011 में शुरू की। 20 फरवरी 2014 को सोहरखा, जाहिदाबाद स्थित राज्य सरकार की 28.9300 हेक्टेयर भूमि का 30 वर्ष के लिए प्राधिकरण के पक्ष में पट्टा अनुबंध किया है।

इसमें 27 खसरा नंबर शामिल थे। प्राधिकरण ने जमीन को 90 वर्ष के पट्टे पर बिल्डरों को आवंटित कर दिया। अफसरों को जब यह पता चला कि भूमि पर उच्च न्यायालय से लेकर सिविल कोर्ट तक 25 से 30 किसानों ने याचिकाएं दायर कर रखी हैं तो 15 खसरा नंबरों की 16.2512 हेक्टेयर भूमि जिला प्रशासन को 24 दिसंबर 2014 वापस कर दिया गया।

नोएडा में दर्दनाक हादसा, सीवर की सफाई के दौरान दो भाइयों की मौत

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 50 स्थित एटीएस ली ग्रांडियोस सोसायटी में सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से दो भाइयों की मौत हो गई। राजू की उपचार के दौरान यथार्थ अस्पताल में मौत हो गई जबकि उनके भाई बबलू की घटना के दिन ही मौत हो गई थी। पीड़ित स्वजन शव लेकर अपने पैतृक गांव हाथरस के सिकंदराराऊ रवाना हो गए हैं।

ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र सेक्टर 50 स्थित एटीएस ली ग्रांडियोस सोसायटी में 18 फरवरी को सीवर की सफाई को अपने भाई के साथ उतरे राजू की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। उसका उपचार यथार्थ अस्पताल में चल रहा था। वे आईसीयू में वेंटिलेटर पर थे। चिकित्सकों की टीम लगातार उन्हें होश में लाने का प्रयास कर रही थी। पीड़ित स्वजन शव लेकर अपने अपने पैतृक गांव हाथरस के सिकंदराराऊ रवाना हो गए। जहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है।

घटना के पांच दिन बाद राजू ने भी तोड़ा दम

ज्ञात हो कि राजू अपने भाई 35 वर्षीय बबलू के साथ सीवर की सफाई करने के लिए उतरा था। सीवर में दोनों जहरीली गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गए थे। उन्हें उपचार के लिए मेंटेनेंस प्रबंधन ने यथार्थ अस्पताल भर्ती कराया था। जहां डॉक्टरों ने बबलू को मृत घोषित कर दिया था। घटना के पांच दिन बाद जिंदगी व मौत से जूझ रहे राजू ने भी आखिरकार हार मान ली।

मृतक के भाई डब्बू ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि उनके दूसरे भाई राजू की भी उपचार के दौरान मौत हो गई है। हालांकि मामले में अभी तक पीड़ित स्वजन ने सोसायटी प्रबंधन के खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी है। सोसायटी प्रबंधन ने पीड़ित स्वजन को बबलू व राजू के परिवार के भरण पोषण व आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है।

डब्बू ने बताया कि अभी परिवार में मातम पसरा हुआ है। वह एक दो दिन बाद ग्रेटर नोएडा आएंगे। ज्ञात हो कि मंगलवार को सोसायटी परिसर के भीतर सफाई करने उतरे बबलू व राजू जहरीली गैस की चपेट में आ गए थे। जिसमें बबलू की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

पूर्व में भी हो चुके हैं हादसे

केस एक

सीवर में सफाई को उतरे सफाईकर्मी पूर्व में भी जहरीली गैस की चपेट में आने से काल के मुंह का ग्रास बन चुके हैं। उसके बाद भी सफाईकर्मियों को बना सुरक्षा उपकरणों के सफाई करने के लिए उतार दिया जाता है।

केस दो

17 मई 2024 को फेस-2 कोतवाली क्षेत्र के होजरी कांप्लेक्स क्षेत्र स्थित रेडीमेड गारमेंट बनाने वाली कंपनी की चोक सीवर को साफ करने उतरे दो सफाईकर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई थी।

केस तीन

चार मई 2024 को थाना सेक्टर 20 में एक मकान के सीवर में सफाई करने उतरे दो मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई थी।

केस चार

25 जून 2024 को ईकोटेक एक कोतवाली क्षेत्र स्थित कोफोर्ज कंपनी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सफाई को उतरे तीन कर्मचारियों की मौत हो गई थी।

कानपुर में सड़क पार करते मासूम को मां से पहले मिली मौत : 6 घंटे जाम

सुनील बाजपेई

कानपुर। तेज रफ्तार ने सड़क सड़क पर खड़ी मां से मिलने से पहले मासूम को मौत से मिलवा दिया। जिसके शिकंजे से धरती के भगवान भी उसे बचा नहीं सके। घटना के विरोध में आक्रोशित परिजनों और गांव वालों में लगभग 6 घंटे तक रोड भी जाम किया ,जिसे पुलिस ने बड़ी मुश्किल से समझाकर खुलवाया।

तेज रफ्तार से एक और मौत की यह घटना बिधनू थाना क्षेत्र में हाजीपुर मोड़ के पास हुई। जहां 3 वर्षीय मासूम आयुष अपनी मां से मिलने के लिए सड़क पार कर रहा था।

उस समय अपनी नानी शिवरानी और बड़े भाई प्रशांत के साथ खेतों से लौट आयुष अपने बड़े भाई का हाथ पकड़कर चल रहा था जबकि मां सोनी सड़क के दूसरी तरफ खड़ी थी।

मां को देखते ही आयुष ने भाई का हाथ छोड़ दिया और उनकी तरफ भागा। इसी दौरान जहानाबाद की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मार दी। सोनी ने बस चालक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रुका। ग्रामीणों के पीछा करने पर चालक बाजपुर मोड़ के पास बस छोड़कर फरार हो गया।

परिजन तुरंत आयुष को निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आक्रोशित परिजनों ने शव को जहानाबाद मार्ग पर रखकर प्रदर्शन किया। उन्होंने स्पीड ब्रेकर लगाने और 15 लाख रुपये मुआवजे की मांग की। प्रदर्शन 6 घंटे तक चला। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस में लोगों को समझा बुझाकर बड़ी मुश्किल से सड़क जाम खुलवाया। पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर घटना की छानवीन के साथ फरार ड्राइवर की भी तलाश की जा रही है।

छापा पड़ते ही मची भगदड़, महिलाओं को इस हालत में देख दंग रह गई पुलिस; पीछे के गेट से कराते थे एंट्री

साहिबाबाद के वैशाली सेक्टर-4 में स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर महिलाओं से देह व्यापार कराने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में पता चला कि मेनगेट पर ताला लगाकर पीछे के गेट से ग्राहकों की एंट्री कराते थे। तीन महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है।

साहिबाबाद। गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद में कौशांबी थाना क्षेत्र के वैशाली सेक्टर-4 स्थित लाजवंती प्लाजा में स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार (Deh Vyapar) का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर महिलाओं से देह व्यापार कराने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में पता चला कि मेनगेट पर ताला लगाकर पीछे के गेट से ग्राहकों की एंट्री कराते थे। तीन महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है। एक मोबाइल, रजिस्टर, समेत अन्य सामग्री मौके से पुलिस ने बरामद की हैं। एसीपी इंदिरापुरम की ओर से मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

तीन महिलाएं आपत्तिजनक स्थिति में मिलीं : कौशांबी थाना क्षेत्र के वैशाली सेक्टर-4 में ब्लिस वेलनेस नाम से स्पा सेंटर है। इसमें मंगलवार को देह व्यापार होने की पुलिस को सूचना मिली थी। सूचना पर सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्वत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच कर छापा मारा। जहां तीन महिलाएं आपत्तिजनक स्थिति में मिलीं। पुलिस ने सेंटर की संचालिक दिल्ली की महिला को गिरफ्तार कर लिया।

कौशांबी थाने में महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज : वहीं, पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि नौकरी के नाम पर उन्हें यहां बुलाया गया। जहां उनसे जबरन देह व्यापार कराया जाने लगा। लोक लिहाज के डर से वह किसी से कुछ नहीं कह पाईं। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री, मोबाइल, क्यूआर कोर्ड समेत अन्य सामान बरामद किया।

पुलिस जांच में सामने आया है कि करीब डेढ़ महीने पहले भी पुलिस ने क्षेत्र में कार्रवाई शुरू की थी तो कुछ दिन के लिए महिला ने बंद कर दिया। इसके बाद फिर से एक माह से इसका संचालन शुरू करा दिया। तीनों महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है। उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है।

सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम ने बताया कि देह व्यापार का धंधा महिला मोबाइल पर संचालिक कर रही थी। इसके लिए वाट्सएप समूह बनाया हुआ था। इसी के जरिए ग्राहकों से फोटो व वीडियो भेजती थी। ग्राहकों से की गई चेट भी मिली है। स्पा सेंटर में बाहर से ताला लगा था, लेकिन पीछे का रास्ता खुला था, जहां से केवल उन लोगों को ही एंट्री मिलती थी, जो व्हाट्सएप के जरिए महिला के संपर्क में आते थे।

22 फरवरी को कौशांबी थाना क्षेत्र के वैशाली सेक्टर पांच के एक फ्लैट में देह व्यापार पकड़ा। संचालक और संचालिका समेत तीन गिरफ्तार

22 जनवरी को कौशांबी थाना क्षेत्र के आयुष होटल में देह व्यापार का पर्दाफाश, संचालक संचालिका समेत आठ गिरफ्तार

20 जनवरी को वैशाली सेक्टर तीन की एल्कान सोसायटी में किराए के फ्लैट में चल रहा देह व्यापार का पर्दाफाश, संचालिका व एक ग्राहक गिरफ्तार

19 जनवरी वैशाली सेक्टर चार के श्रीराम प्लाजा में दो स्पा सेंटर की आड में देह व्यापार का पर्दाफाश संचालक-संचालिका समेत पांच गिरफ्तार

ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट की ज़बरदस्त घेराबंदी - यूएन वोटिंग में रूस का साथ-यूरोपीय यूनियन दंग-यूक्रेन धड़ाम - खनिज़ संपादा देने पर राज़ी !

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं
गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तपर भारतीय कहावतें पूरी दुनियाँ सहित युद्ध पीड़ित देशों पर भी लागू हो रही है जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत होने के बाद जिधर दम उधर हम,जिसकी लाठी उसी की भैंस, मेरी मुर्गी की एक टांग, जहां हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, इत्यादि अनेक कहावतें एक झटके से लागू हो रहे हैं ! जी हां हम बात कर रहे हैं अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले उन्होंने चुनावी सभा में किए गए वादों को पूरा करने की झड़ी सी लगा दीहै अवैध प्रवासी को बाहर का रास्ता, टैरिफ लगाना, यूक्रेन रूस युद्ध को समाप्त करवाने की प्रक्रिया शुरू करने के बाद अब अमेरिकी फर्स्ट, की तर्ज पर अर्थव्यवस्था में भारी सुधार के नाम पर रूस से बातचीत को मोहरा बनाकर यूक्रेन से खनिज संपत्ती लेना जो एक तरह का यूक्रेन को युद्ध में साथ देने की फीस है पनामा से नहर को लेना इत्यादि अनेक सुधारो की एक झड़ी सी लग गई है तो उधर यूरोपीय संघ को अलग-अलग करने की भी गुंजाइश दिख रही है, जिसे यूरोपीय यूनियन भी दंग है,वह अमेरिका से अलग-थलग यूक्रेन के साथ शिखर सम्मेलन हो रहे हैं उधर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन मुद्दे पर रुस के पक्ष में वोटिंग कर दुनियाँ को चौंका दिया है। मेरा मानना है कि इन सब नीतिओं रणनीतियों के पीछे पनामा से नहर, यूक्रेन से खनिज संपदा व अनेक देशों से टैरिफ के रूप में भारी मात्रा में धन- इकट्ठा कर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत व अपने अमेरिकी फर्स्ट की विचारधारा व लक्ष्य यानें विज़न को आगे बढ़ाना है इन सब के बीच पूरी दुनियाँ की नजरे ट्रंप जेलेंस्की की शुक्रवार को हो रही बैठक पर लगी हुई है। चूँकि यूएन में अमेरिका ने रूस का साथ देकर दुनियाँ को चौकाया है, आखिर झुक गया ही रूक्रेन, क्या इस पूरी प्रक्रिया में रुस भी मोहरा बन गया ? तथा अमेरिकी फर्स्ट के आगे यूक्रेन ने घुटने टेके ? अमेरिका से खनिज संबंधी शर्त पर सहमति कर शुक्रवार को वाशिंगटन में बातचीत होगी, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की जबरदस्त घेराबंदी, यूएन में रूस का साथ, यूरोपीय यूनियन दंग,यूक्रेन धड़ाम,खनिज संपदा देने पर राजी हो गया है !

साथियों बात अगर हम 25 फ़रवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन मुद्दे पर चुनाव में अमेरिका ने रूस को साथ देने की करें तो,अमेरिका के एक कदम से यूक्रेन और राष्ट्रपति जेलेंस्की को बड़ा झटका लगा है ।संयुक्त राष्ट्र के तीन प्रस्तावों पर मतदान के दौरान अमेरिका रूस के साथ खड़ा नज़र आया। यूएन में यूरोपीय संघ और यूक्रेन की ओर से रूस के हमले की निंदा से जुड़ा एक प्रस्ताव पेश किया गया था लेकिन, अमेरिका ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। अमेरिका के इस कदम से यूएस और यूरोप के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका है, दोनों के रिश्तों में थोड़ी तल्खी भी आई है ।इसके अलावा रूस-यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के बदलते रुख ने एक नया संदेह को भी जन्म दे दिया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 93, विपक्ष में 18 और 65 मतों के साथ पारित किया गया ।बता दें रूस और यूक्रेन में बीते तीन साल से जारी युद्ध को खत्म करने की मांग करते हुए संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश किया गया था, प्रस्ताव में रूस की आक्रामकता की निंदा की गई थी और रूसी सैनिकों की तत्काल वापसी की मांग की गई थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका और रूस ने यूरोप समर्थित यूक्रेन के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था इसके बाद अमेरिका ने अपने प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव पर मतदान से खुद को अलग कर लिया था। अमेरिका की इस नीति से यूक्रेन को जोरदार झटका लगा है ।संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के पास वीटो की शक्ति है। 15 सदस्यीय परिषद में शून्य के मुकाबले 10 वोट से मतदान हुआ और पांच देश मतदान से दूर रहे। ये सभी यूरोपीय देश थे। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने संघर्ष के जल्द से जल्द समाधान के लिए रूस के साथ अचानक बातचीत शुरू की जिससे यूक्रेन के साथ अमेरिका के रिश्ते में तल्खी आई है, यूरोपीय नेता भी इस बात से निराश हैं कि पिछले सप्ताह उन्हें और यूक्रेन को रूस के साथ प्रारंभिक वार्ता से बाहर रखा गया था ।मीडिया में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक मतदान में महासभा ने यूक्रेन को लेकर प्रस्ताव पर 18 के मुकाबले 93 मतों से मंजूरी दी, जबकि 65 सदस्यों ने मतदान नहीं किया था इसके

कारण यूक्रेन के लिए समर्थन कम होता दिख रहा है, क्योंकि पिछले मतदान में 140 से अधिक देशों ने रूस के हमले की निंदा की थी और उससे तत्काल सैनिकों की वापसी की मांग की थी। इसके बाद सभा ने रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान हुई आम लोगों की मौत संबंधी अमेरिका के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी ।प्रस्ताव में संघर्ष को जल्द खत्म करने और यूक्रेन-रूस के बीच स्थायी शांति की अपील की गई थी , हालांकि इसमें रूस की आक्रामकता का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था ।बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बीते करीब तीन सालों से जारी है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर हमला कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका सहित यूरोप के कई देशों से मदद की मदद ले रहे हैं, हालांकि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद नये शासक ट्रंप की यूक्रेन-रूस को लेकर नीतियों में थोड़ा बदलाव आया है, जिसकी बानगी मतदान के दौरान भी नजर आई थी।

साथियों बात अगर हम अमेरिका यूक्रेन में खनिज संपदा आर्थिक समझौते पर यूक्रेन के झुकाने की करें तो, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बुधवार को कहा कि अमेरिका के साथ एक रूपरेखा आर्थिक समझौता तैयार है, लेकिन रूस के साथ युद्ध में कीव के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाली अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर अभी फैसला होना बाकी है और पूर्ण समझौता शुक्रवार को वाशिंगटन में होने वाली वार्ता पर निर्भर करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है किजेलेंस्की शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण खनिज सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिका आएंगे। ट्रंप ने बुधवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक की शुरुआत में यह घोषणा की ।जेलेंस्की ने कीव में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिस रूपरेखा समझौते पर सहमति बनी है, वह एक व्यापक समझौते की दिशा में एक प्रारंभिक कदम है, जिस पर यूक्रेन की संसद की मंजूरी की जरूरत होगी। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को पहले यह जानना होगा कि अमेरिका अपने निरंतर सैन्य समर्थन के मामले में कहां खड़ा है। उन्होंने कहा कि उन्हें वाशिंगटन की यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ व्यापक बातचीत की उम्मीद है ।उन्होंने कहा,यह (आर्थिक) समझौता भविष्य की सुरक्षा गारंटी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मैं व्यापक दृष्टिकोण को समझना चाहता हूं। पिछले महीने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से ट्रंप ने यूक्रेन को बता दिया कि वह रूस द्वारा तीन साल पहले 24 फरवरी, 2022 को शुरू किए गए आक्रमण को रोकने के लिए अमेरिका से अरबों डॉलर की मदद के बदले में कुछ चाहते हैं ।व्हाइट हाउसके एक अधिकारी ने बुधवार को फिर से स्पष्ट किया कि समझौते को स्वीकार करना शुक्रवार को जेलेंस्की को मिलने के लिए ट्रंप के निमंत्रण की एक आवश्यक शर्त थी। जेलेंस्की ने कहा, 'यह समझौता या तो बहुत सफल हो सकता है या चुपचाप खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि सफलता राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारी बातचीत पर निर्भर करती है। मैं अमेरिका के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ समन्वय करना चाहता हूं।

साथियों बात अगर हम रुस को मोहरा बनाकर यूक्रेन पर दबाव बनाकर खनिज संपदा हथियाना व उन खनिजों को जानने की करें तो,जब से ये खबर आई है किट्रंप दुर्लभ खनिजों के लिए यूक्रेन से डील करने जा रहे हैं, तब से दुनियाँ भर में हलचल है, ट्रंप ने पहले तो दुत्कारा और रूस को पुचकारा, फिर ये डील ! वो भी रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए ! ये न सिर्फ दुर्लभ है बल्कि बेशकीमती भी हैं जिसके पास ये है उसकी इकॉनमी भी कुलांचे भरेंगी,तो आखिर ये है क्या ? रेयर अर्थ मिनरल्स 17 रासायनिक रूप से समान तत्वों का एक समूह है, जो पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाते हैं। इन्हें अक्सर एक साथ रखा जाता है क्योंकि इनकी विशेषताएँ मिलती-जुलती हैं, ये तत्व आधुनिक तकनीकों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, और रक्षा प्रणालियाँ !17 रेयर अर्थ तत्वों में शामिल हैं: लैंथेनम, सेरियम,प्रसी ओडाइमियम, सी नियोडाइमियम प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस प्रोसियम,होल्मियम,एर्बियम,थुलियम यिट्रबियम, लुटेटियम, यिट्रियम, (इसे अक्सर रेयर अर्थ तत्व माना जाता है, हालांकि यह लैंथेनाइड श्रृंखला का हिस्सा नहीं है) अब सवाल उठता है कि अमेरिका क्यों चाहता है यूक्रेन से ये निकाला जाए, इसके कई कारण हैं (1) अमेरिका अपनी आपूर्ति के लिए अलग-अलग देशों पर निर्भर होना चाहता है। अभी, चीन दुनिया को सबसे ज़्यादा दुर्लभ धातुएँ देता है। इससे अमेरिका को चिंता है कि चीन इन धातुओं की कीमतें बढ़ा सकता है या उनकी सप्लाई रोक सकता है। (2) अमेरिका और चीन के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। इसलिए अमेरिका अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद बनाना चाहता है। यूक्रेन में बहुत सारी दुर्लभ धातुएँ हैं और वह अमेरिका का साथ दे सकता है। (3) यूक्रेन में बहुत सारी दुर्लभ धातुएँ हैं लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अमेरिका यूक्रेन को इन धातुओं को निकालने में मदद कर सकता है। इससे यूक्रेन की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और अमेरिका को धातुएँ भी मिलेंगी। (4) दुर्लभ धातुओं का इस्तेमाल नई तकनीकों जैसे सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और कंप्यूटर बनाने में होता है। अमेरिका को डर है कि अगर उसे ये धातुएँ नहीं मिलीं तो वह नई तकनीक नहीं बना पाएगा। (5) रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। दुर्लभ धातुओं के व्यापार से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और वह रूस से लड़ने में सक्षम होगा ।इस तरह, अमेरिका यूक्रेन को दुर्लभ धातुओं का एक नया स्रोत मानता है। इससे अमेरिका को अपनी ज़रूरत की धातुएँ मिलेंगी और यूक्रेन को भी उसमे बहुत मदद मिलेगी।

साथियों बात अगर हम यूरोपियन यूनियन की स्थिति की करें तो, इन यूरोपीय शक्तियों का कहना है कि हमारा साझा उद्देश्य यूक्रेन को एक मजबूत स्थिति में लाने का होना चाहिए। ताकि यूक्रेन को एक मजबूत सुरक्षा गारंटी प्रदान की जा सके। साथ ही वहां एक न्यायसंगत स्थायी शांति ट्रांस अटलांटिक सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। यूरोपीय देशों ने एक सुर में कहा है कि अमेरिकी सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलना चाहती हैं। इस मामले में फ्रांस के विदेश मंत्री ने बुधवार को ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, इटली, स्पेन, यूक्रेन और यूरोपियन कमीशन के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी इस नतीजे पर पहुंचे कि यूक्रेन को लेकर यूरोपीय देशों की भागीदारी के बिना किया गया कोई भी फैसला स्थायी शांति नहीं ला सकेगा। वहीं जर्मनी ने इस मामले में यूरोपीय यूनियन से एकजुट होने का आह्वान किया है। स्पेन का कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि यूक्रेन में शांति हो, लेकिन अन्यायपूर्ण तरीके से शुरू हुआ ये युद्ध न्यायपूर्ण तरीके से समाप्त होना चाहिए।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट की ज़बरदस्त घेराबंदी-यूएन वोटिंग में रूस का साथ-यूरोपीय यूनियन दंग-यूक्रेन धड़ाम- खनिज़ संपादा देने पर राज़ी !यूएन में अमेरिका ने रूस का साथ देकर दुनियाँ को चौंकाया-आखिर झुक गया यूक्रेन ?- क्या रूस भी मोहरा बना ?अमेरिकी फर्स्ट के आगे यूक्रेन ने घुटने टेके-अमेरिका से खनिज़ समझौते पर सहमत- शुक्रवार को वाशिंगटन में बातचीत।

मारुति ई विटारा कितनी होगी सुरक्षित, लॉन्च से पहले सामने आई क्रैश टेस्ट की जानकारी

परिवहन विशेष न्यूज

भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। मारुति की ओर से जल्द ही पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर E-Vitara को लाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने एसयूवी का क्रैश टेस्ट किया है। लॉन्च से पहले क्रैश टेस्ट को लेकर क्या जानकारी सामने आई है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में ऑफर की जाने वाली कारों को लगातार सुरक्षित बनाने पर काम किया जा रहा है। प्रमुख वाहन निर्माता Maruti की ओर से भी जल्द ही पहली Electric SUV के तौर पर E Vitara को लॉन्च किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉन्च से पहले इसका क्रैश टेस्ट (Maruti E Vitara Crash Test) किया गया है। जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो गई हैं। इन फोटो से टेस्ट की क्या जानकारी मिल रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti E Vitara का हुआ Crash Test

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति की ओर से पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर जल्द ही लॉन्च की जाने वाली E Vitara का Crash Test किया गया है। हाल में हुए इस क्रैश टेस्ट की फोटो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो गई हैं। हालांकि अभी कंपनी की ओर से इस बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है।

क्या मिली जानकारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी का क्रैश टेस्ट B-NCAP या Global NCAP की ओर से नहीं किया गया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि कंपनी की ओर से ही आंतरिक टेस्ट किया गया हो। हालांकि अभी सिर्फ इसकी फोटो ही सार्वजनिक हुई हैं, किसी भी तरह के परिणाम की जानकारी सामने नहीं आई है।

क्रैश टेस्ट में मिल सकती है बेहतर रेटिंग

मारुति की ओर से ऑफर की जाने वाली इस एसयूवी को औपचारिक तौर पर क्रैश टेस्ट होने के बाद बेहतर रेटिंग मिल सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कंपनी की ओर से इसमें कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर दिए जा रहे हैं। जिससे इसकी क्रैश टेस्टिंग बेहतर हो सकती है।

कैसे हैं सेफ्टी फीचर्स

Maruti E Vitara में कंपनी की ओर से सात एयरबैग, टीपीएमएस, एबीएस, ईबीडी, 360 डिग्री कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर, हिल असिस्ट जैसे कई सेफ्टी फीचर ऑफर किए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें ADAS जैसे सेफ्टी फीचर को भी दिया जाएगा।

कितनी होगी रेंज

मारुति की ओर से इसमें 61 kWh की क्षमता की बैटरी को दिया जाएगा। जिसे फुल चार्ज के बाद 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक चलाया जा सकेगा। इसके अलावा इसमें एक और बैटरी के विकल्प के तौर पर 49 kWh को भी दिया जा सकता है। जिससे कम रेंज मिलेगी, लेकिन इससे गाड़ी की कीमत कम करके ऑफर किया जा सकता है।

कब होगी लॉन्च

कंपनी की ओर से अभी E Vitara के लॉन्च को लेकर किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन यह बताया गया है कि पहले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा और उसके बाद ही गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में इस बात की संभावना ज्यादा है कि इसे फेस्टिव सीजन के पहले औपचारिक तौर पर लॉन्च कर दिया जाए।

कितनी होगी कीमत

मारुति की ओर से एसयूवी को लॉन्च करने के बाद ही कीमतों की जानकारी दी जाएगी। लेकिन इसे मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में लाया जाएगा। ऐसे में इसकी एक्स शोरूम कीमत 20 लाख रुपये के आस-पास हो सकती है।

किनसे होगा मुकाबला

मारुति की ओर से पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर E Vitara को लाया जाएगा। इस एसयूवी का बाजार में सीधा मुकाबला Hyundai Creta Electric और जल्द लॉन्च होने वाली Tata Harrier के साथ होगा।

किआ कर रही सेल्टॉस को और बेहतर करने की तैयारी, लॉन्च से पहले टेस्टिंग के दौरान दिखी SUV

परिवहन विशेष न्यूज

साउथ कोरियाई की वाहन निर्माता Kia की ओर से कई सेगमेंट में एमपीवी और एसयूवी की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी जल्द ही नई जेनरेशन सेल्टॉस को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। नई जेनरेशन सेल्टॉस को हाल में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। एसयूवी की क्या जानकारी सामने आई है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। कई देशों में बेहतरीन तकनीक, फीचर्स और इंजन के साथ अलग अलग सेगमेंट में Cars and SUVs को ऑफर करने वाली साउथ कोरियाई वाहन निर्माता Kia की ओर से जल्द ही New Generation Kia Seltos को लॉन्च करने की तैयारी (Kia Seltos facelift Upgrade) की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसकी टेस्टिंग कर रही है। टेस्टिंग के दौरान किन फीचर्स की जानकारी सामने आई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

आएगा Kia Seltos का Facelift

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किआ की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली सेल्टॉस के फेसलिफ्ट वर्जन को लाने की तैयारी की जा रही है। कंपनी की ओर से अभी इस बारे में औपचारिक तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

क्या मिली जानकारी

टेस्टिंग के दौरान देखी गई एसयूवी को पूरी तरह ढका गया था, लेकिन इसकी हेडलाइट और फ्रंट लुक की जानकारी हाल में ही सामने आई है। जिसके मुताबिक मौजूदा जेनरेशन के मुकाबले नई जेनरेशन एसयूवी के फ्रंट में कई बदलाव किए जा सकते हैं। एसयूवी में नए डिजाइन की हेडलाइट्स को भी दिया जा सकता है। इसमें नए डिजाइन वाली वर्टिकल एलईडी डीआरएल के साथ ही लाइट्स को दिया जा सकता है। इसके अलावा इसके रियर में भी नए डिजाइन वाली थीम के साथ मिलते हुए डिजाइन को लाया जा सकता है। गाड़ी में कुछ नए फीचर्स (Kia Seltos new features) को भी जोड़ा जा सकता है, जिसमें ज्यादा पार्किंग सेंसर, लोअर ग्रिल के साथ ADAS सिस्टम को दिया जा सकता है।

Kia Syros की तरह हो सकता है इंटीरियर

सेल्टॉस के नीचे पोजिशन की गई सिरोस में जिस तरह का इंटीरियर ऑफर किया गया है, उसी से प्रेरित इंटीरियर को नई सेल्टॉस में लाया जा सकता है। इसमें भी डबल डी-कट स्टेयरिंग व्हील, 30 इंच की ट्रिनिटी डिस्प्ले, स्लाइडिंग और रिक्लाइन होने वाली रियर सीट को दिया जा सकता है।

इंजन में नहीं होगा कोई बदलाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी के इंजन में किसी भी तरह के बदलाव को नहीं किया जाएगा। इसमें मौजूदा जेनरेशन की तरह ही 1.5 लीटर की क्षमता का नेचुरल एस्पिरेटिड, टर्बो पेट्रोल इंजन के अलावा टर्बो डीजल इंजन दिया जाएगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से हाइब्रिड इंजन के विकल्प को भी नई सेल्टॉस में दिया जा सकता है।

कब तक आएगी भारत

फिलहाल किआ की ओर से सेल्टॉस को दुनिया के कई देशों के अलावा भारतीय बाजार में भी ऑफर किया जा रहा है। नई जेनरेशन की फिलहाल टेस्टिंग चल रही है। जिसके बाद प्रोडक्शन तक आने और लॉन्च होने में एक से दो साल का समय लग सकता है। भारत में भी इस एसयूवी को साल 2026 के आखिर या 2027 तक लाया जा सकता है।

किनसे है मुकाबला

किआ सेल्टॉस को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta, Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder, Honda Elevate, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun, MG Hector, Tata Harrier, Mahindra ScorpioN जैसी दमदार एसयूवी के साथ होता है।

रेनो कर रही सब फॉर मीटर एसयूवी किगर के फेसलिफ्ट को लाने की तैयारी, लॉन्च से पहले टेस्टिंग के दौरान मिली यह जानकारी

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय बाजार में Sub Four Meter SUV सेगमेंट में कई कंपनियों की ओर से अपने उत्पादों को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेनो की ओर से ऑफर की जाने वाली काइगर एसयूवी के फेसलिफ्ट को लाने की तैयारी की जा रही है। लॉन्च से पहले टेस्टिंग के दौरान इसकी क्या जानकारी सामने आई है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में सबसे ज्यादा एसयूवी सेगमेंट के वाहनों की बिक्री होती है। इसमें भी Sub Four Meter सेगमेंट में सबसे ज्यादा विकल्प ऑफर किए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सेगमेंट में आने वाली Renault Kiger के फेसलिफ्ट को लाने की तैयारी की जा रही है। लॉन्च से पहले इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। Renault Kiger facelift के बारे में क्या जानकारी सामने आई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Renault Kiger का आएगा फेसलिफ्ट

रिपोर्ट्स के मुताबिक रेनो की ओर से काइगर एसयूवी के फेसलिफ्ट को लाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी कंपनी की ओर से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे फेस्टिव सीजन के पहले लॉन्च किया जा सकता है।

क्या मिली जानकारी

लॉन्च से पहले कंपनी इसके फेसलिफ्ट वर्जन को टेस्ट कर रही है। टेस्टिंग के दौरान इसे देखा गया है। जिसके मुताबिक एसयूवी के फ्रंट में मामूली बदलाव किए जा सकते हैं। गाड़ी की साइड प्रोफाइल भी मौजूदा वर्जन की तरह ही हो सकती है और रियर से भी कुछ बदलावों के साथ इसे लाया जा सकता है। वहीं इंटीरियर में डैशबोर्ड के आस-पास बदलाव किए जा सकते हैं और कुछ नए फीचर्स को जोड़ा जा सकता है।

2025 में मिले ये फीचर्स

कंपनी की ओर से 2025 काइगर में आठ इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। इसके अलावा इसमें सात इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑफर किया गया है। गाड़ी में वायरलेस चार्जर और एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले जैसे फीचर्स को भी दिया गया है।

इंजन में नहीं होगा बदलाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ी के इंजन में किसी भी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें मौजूदा वर्जन वाले इंजन को ही ऑफर किया जाएगा। Renault Kiger में कंपनी की ओर से एक लीटर नेचुरल एस्पिरेटिड इंजन दिया जाता है जिससे 72 पीएस की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 5स्पीड मैनुअल और 5स्पीड एएमटी ट्रांसमिशन का विकल्प दिया जाता है। दूसरे विकल्प के तौर पर इसमें एक लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाता है जिससे इसे 100 पीएस की पावर और 160 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। इसमें 5स्पीड मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन के विकल्प को दिया जाता है।

ओला के स्कूटर और बाइक्स की बैंड बजाने अल्ट्रावॉयलेट कर रही तैयारी, पांच मार्च को करेगी बड़ी घोषणा

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में Electric Vehicle सेगमेंट में लगातार नए वाहनों को पेश और लॉन्च किया जा रहा है। इसी क्रम में Ultraviolette भी अब अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। औपचारिक तौर पर कंपनी कब तक नए वाहनों को पेश करने की घोषणा करेगी। किन सेगमेंट्स में वाहनों को लाया जाएगा। इससे OLA सहित किन कंपनियों को चुनौती मिलेगी। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में सामान्य Electric Vehicles के साथ ही परफॉर्मेंस सेगमेंट में भी बाइक्स को ऑफर किया जाता है। देश की स्टार्टअप Ultraviolette की ओर से भी जल्द ही कई नए उत्पादों को लाने की तैयारी की जा रही है। कंपनी की ओर से किस तरह के उत्पादों को लाया जा सकता है। कब तक इनकी घोषणा की जा सकती है। इससे किन कंपनियों को कड़ी चुनौती मिल सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Ultraviolette Announces New Electric Vehicles to Challenge Ola

स्टार्टअप Ultraviolette की ओर से जल्द ही नए वाहनों को लाने की तैयारी की जा रही है। कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है कि वह दो पहिया सेगमेंट में कई नए वाहनों को लाएगी। जिससे कई कंपनियों को चुनौती मिलेगी।

Major Electric Vehicle Launch Set for March Announcement

कंपनी की ओर से पांच मार्च 2025 को भविष्य में लाए जाने वाले वाहनों को लेकर जानकारी दी जाएगी। लेकिन सभी वाहनों को एक साथ नहीं जाएगा, बल्कि इनको अलग अलग फेज़ में कंपनी की ओर से पेश और लॉन्च किया जाएगा।

किस तरह के वाहनों को लाया जाएगा

फिलहाल कंपनी की ओर से यह जानकारी नहीं दी गई कि वह किस सेगमेंट में किस तरह के दो पहिया वाहनों को ला सकती है। लेकिन अल्ट्रावायलेट की ओर से जारी की गई फोटो में छह वाहनों को दिखाया गया है। इनमें से पांच बाइक्स और एक को स्कूटर सेगमेंट में लाया जा सकता है।

क्या होंगी खासियत

अल्ट्रावायलेट की ओर से कई सेगमेंट में इन वाहनों को लाया जाएगा। जिनमें बजट सेगमेंट से लेकर लग्जरी सेगमेंट तक के वाहन शामिल होंगे। इनमें F77 जैसे फीचर्स और तकनीक को दिया जा सकता है। साथ ही कई नए फीचर्स के साथ इनको ऑफर किया जाएगा।

अधिकारियों ने कही यह बात

अल्ट्रावायलेट के सीईओ और को-फाउंडर नारायण सुब्रमण्यम ने कहा कि हमने सात साल पहले F77 से अपने सफर को शुरू किया था। इस दौरान हमने कई तरह की रिसर्च की और कुछ उत्पादों को डेवलप किया। हमने बैटरी, मोटर, सेफ्टी जैसे मोर्चों पर काफी काम किया है, जिससे हमारा आधार काफी ज्यादा मजबूत हुआ है। जिसके बाद हम नए चरण में नए वाहनों को लाने की तैयारी कर रहे हैं, जो अलग अलग सेगमेंट में होंगे और नए मानक स्थापित करेंगे।

किसे मिलेगी चुनौती

अल्ट्रावायलेट की ओर से बाजार में फिलहाल F77 जैसी परफॉर्मेंस बाइक को ऑफर किया जाता है। इसके अलावा कंपनी की ओर से कई सेगमेंट में नए वाहनों को लाने की तैयारी की जा रही है। जिसमें स्कूटर और बाइक शामिल होंगे। ऐसे में Ola, Ather, TVS, Bajaj, Revolt, Matter, Oben, Simple जैसे निर्माताओं को कड़ी चुनौती मिल सकती है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन कार्बन एडिशन वर्सेज एमजी हेक्टर ब्लैकस्टॉर्म एडिशनः इंजन, फीचर्स और कीमत में किस एसयूवी को खरीदें

परिवहन विशेष न्यूज

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन कार्बन एडिशन वर्सेज एमजी हेक्टर ब्लैकस्टॉर्म एडिशन महिंद्रा की ओर से 24 February 2025 को ही Scorpio N के कार्बन एडिशन को लॉन्च किया गया है। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में स्कॉर्पियो के पहले MG की ओर से भी Hector के Blackstorm Edition को लॉन्च किया जा चुका है। दोनों एसयूवी के खास एडिशन में क्या खासियत दी गई हैं। किस कीमत पर इनको खरीदा जा सकता है।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लोगों की पसंद को देखते हुए कंपनियों की ओर से इन एसयूवी को ब्लैक एडिशन के साथ ऑफर करवाया जाता है। Mahindra की ओर से Scorpio N के Carbon Edition को फरवरी 2025 में लाया गया है और MG भी Hector को Blackstorm Edition के साथ ऑफर करती है। दोनों एसयूवी के इन खास एडिशंस में किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं। कितना दमदार इंजन दिया गया है। किस कीमत पर इनको खरीदा जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

महिंद्रा की ओर से 24 February 2025 को ही स्कॉर्पियो एन के कार्बन एडिशन को लॉन्च किया गया है। बाजार में इसका सीधा मुकाबला MG Hector Blackstorm Edition के साथ होता है। दोनों को ही कंपनियों की ओर से फुल ब्लैक थीम को रखा गया है। लेकिन एमजी की ओर से हेक्टर के खास एडिशन में कई जगहों पर रेड कलर इंसर्ट्स को भी दिया जाता है।

Carbon Edition Vs Blackstorm Edition Features

Mahindra Scorpio N के Carbon Edition में कंपनी की ओर से ईएससी, हिल होल्ड, एबीएस, ईबीडी, डीडीडी, पार्किंग सेंसर, एयरबैग, टीपीएमएस, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, ई-कॉल, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज, फ्रंट वेंटिलेटिड सीट्स, इंजन स्टार्ट/स्टॉप, ड्यूल जोन एसी, एड्रेनॉक्स, 12 स्पीकर के साथ ऑडियो सिस्टम, 17.78 सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले, वायरलेस चार्जिंग, स्टेयरिंग कंट्रोल्स, फ्रंट और रियर कैमरा, चार्जिंग पोर्ट, पुश बटन स्टार्ट, सनरूफ, एलईडी लाइट्स, हाई ग्लॉस सेंटर कंसोल जैसे फीचर्स को दिया गया है।

वहीं MG Hector Blackstorm Edition को पियानो ब्लैक रूफ रेल, डार्क क्रोम इंसर्ट के साथ फ्रंट और रियर स्किड प्लेट, ब्लैक स्मोक्ड एलईडी कनेक्टिड टेल लाइट्स, पियानो ब्लैक बैजल के साथ एलईडी प्रोजेक्टर लैंप, 18 इंच ब्लैक अलॉय व्हील्स, सीक्वेंशनल इंडीकेटर्स, पैनोरमिक सनरूफ, 14 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्लैक्ड थीम इंटीरियर, एंबिएंट लाइट्स, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील, ड्यूल जोन ऑटो एसी, एयर प्यूरीफायर, ऑटो हेडलैंप, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, वेंटिलेटिड सीट्स, वायरलेस चार्जर, 360 डिग्री कैमरा, छह एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, एयरबैग, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, ईपीबी, ईएसपी, टीपीएमएस, पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज, पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं।

Carbon Edition Vs Blackstrom Edition Engine

Mahindra Scorpio N Carbon Edition के इंजन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। एसयूवी में दो लीटर की क्षमता का पेट्रोल और 2.2 लीटर की क्षमता के डीजल इंजन का ही उपयोग किया गया है। इसके साथ ही एसयूवी के ब्लैक एडिशन में मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प को दिया गया है। एसयूवी के कार्बन एडिशन में भी 4WD के विकल्प को दिया गया है।

वहीं MG Hector Blackstorm Edition में कंपनी की ओर से 1.5 लीटर की क्षमता का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाता है। जिससे 143 पीएस की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। दूसरे विकल्प के तौर पर दो लीटर की क्षमता का टर्बो डीजल इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 170 पीएस की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें 6स्पीड ऑटोमैटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है।

Carbon Edition Vs Blackstorm Edition Price

महिंद्रा स्कॉर्पियो के कार्बन एडिशन की शुरूआती एक्स शोरूम कीमत 19.19 लाख रुपये रखी गई है और इसके टॉप वेरिएंट को 24.89 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है।

वहीं MG Hector Blackstorm को भारतीय बाजार में सिर्फ एक ही वेरिएंट में दिया गया है और उसे 22.14 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है।

अधिसंख्य आबादी तक पहुंचें सस्ती दवाइयां

विजय गर्ग

आमतौर पर सभी दवाओं में एक तरह का 'केमिकल सॉल्ट' होता हैं। इन्हें शोध के बाद अलग-अलग बीमारियों के लिए बनाया जाता है। जेनेरिक दवा जिस सॉल्ट से बनी होती है, उसी के नाम से जानी जाती है। जैसे दर्द और बुखार में काम आने वाले पैरासिटामोल सॉल्ट को कोई कंपनी इसी नाम से बेचे तो उसे जेनेरिक दवा कहेंगे। वहीं, जब इसे किसी ब्रांड (जैसे क्रोसिन) के नाम से बेचा जाता है तो यह उस कंपनी की ब्रांडेड दवा कहलाती है।

पिछले काफी समय से जेनेरिक या ब्रांडेड दवाओं पर बहस छिड़ी है। पिछले साल नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक नियम लागू किया था। इसमें कहा गया था कि डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं भी लिखनी होंगी। नियम न मानने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनएमसी के इस फैसले के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस नियम पर सवाल खड़े किए थे। कई डॉक्टर एसोसिएशन ने भी नए कानून का विरोध कर इसको वापस लेने की मांग की थी। तर्क यह दिया गया था कि ब्रांडेड दवा न लिखने से मरीजों को नुकसान हो सकता है। विरोध के बाद एनएमसी ने अपना फैसला वापस ले लिया था। सरकार मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है। इसके बाद डॉक्टर्स को मरीजों के लिए सिर्फ जेनेरिक दवा लिखनी होंगी, न कि किसी विशेष ब्रांड या कंपनी की। इसके बाद भी मरीजों को सस्ती दवाएं मिलने लगेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जेनेरिक दवाओं के चलन से बड़ी फार्मा कंपनियों को सीधे नुकसान होगा।

आमतौर पर सभी दवाओं में एक तरह का 'केमिकल सॉल्ट' होता हैं। इन्हें शोध के बाद अलग-अलग बीमारियों के लिए बनाया जाता है। जेनेरिक दवा जिस सॉल्ट से बनी होती है, उसी के नाम से जानी जाती है। जैसे दर्द और बुखार में काम आने वाले पैरासिटामोल सॉल्ट को कोई कंपनी इसी नाम से बेचे तो उसे जेनेरिक दवा कहेंगे। वहीं, जब इसे किसी ब्रांड (जैसे क्रोसिन) के नाम से बेचा जाता है तो यह उस कंपनी की ब्रांडेड दवा कहलाती है।

जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड की तुलना में 10 से 20 गुना तक सस्ती होती हैं। दरअसल, फार्मा कंपनियां ब्रांडेड दवाइयों की रिसर्च, पेटेंट और विज्ञापन पर

काफी पैसा खर्च करती हैं। जबकि जेनेरिक दवाइयों की कीमत सरकार तय करती है और इसके प्रचार-प्रसार पर ज्यादा खर्च भी नहीं होता।

कई जानलेवा बीमारियां जैसे एचआईवी, लंग कैंसर, लीवर कैंसर में काम आने वाली दवाओं के ज्यादातर पेटेंट बड़ी-बड़ी कंपनियों के पास हैं। वे इन्हें अलग-अलग ब्रांड से बेचती हैं। अगर यही दवा जेनेरिक में उपलब्ध हो तो इलाज पर खर्च 200 गुना तक घट सकता है। जैसे एचआईवी की दवा टेनोफिविर या एफाविरेज़ की ब्रांडेड दवा का खर्च 2,500 डॉलर यानी करीब 1 लाख 75 हजार रुपये है, जबकि जेनेरिक दवा में यही खर्च 12 डॉलर यानी महज 840 रुपये महीने तक हो सकता है। हालांकि, इन बीमारियों का इलाज ज्यादातर सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में होता है। ऐसे में ये दवाएं इन अस्पतालों में या वहां के केमिस्ट के पास ही मिल पाती हैं।

देश में फार्मा इंडस्ट्री 1.20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की है और इसकी सालाना ग्रोथ 11 प्रतिशत है। देश में सालाना करीब 1.27 लाख करोड़ की दवाएं बेची जाती हैं, इसमें 75 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा जेनेरिक दवाओं का है। भारत जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनियाभर की डिमांड की 20 प्रतिशत दवाइयां भारत सप्लाई करता है। अमेरिका में 40 प्रतिशत और यूके में 25 प्रतिशत दवाइयां भारत सप्लाई करता है। 2018-19 में देश से 1,920 करोड़ डॉलर की दवाइयां एक्सपोर्ट की गईं। दुनियाभर में कुल वैक्सीन डिमांड का 50 प्रतिशत भारत से सप्लाई होता है। इनके अलावा दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राजील, नाइजीरिया और जर्मनी में भी भारतीय दवाएं एक्सपोर्ट की गईं।

एक अनुमान के मुताबिक, किसी भी मरीज के इलाज के दौरान होने वाले खर्च का 70 प्रतिशत अकेले दवाओं पर खर्च हो जाता है। सरकार ने पिछले महीने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि इलाज और दवा पर होने वाले खर्च की वजह से देश में हर साल 3 करोड़ 8 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। फिलहाल सरकार की आयुष्मान भारत योजना से निःशुल्क इलाज और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती जेनेरिक दवाओं का मिलना लोगों के लिए राहत की बात है। आयुष्मान भारत योजना का दायरा देश की अधिसंख्य आबादी तक बढ़ाने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य लोगों को ब्रांडेड महंगी दवाइयों के स्थान पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां प्रदान करना है। सरकार के प्रयास के बावजूद अभी भी देश में बड़े पैमाने पर जेनेरिक दवाओं का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। समय आ गया है कि सामुदायिक स्तर पर जेनेरिक दवाओं को प्रोत्साहित किया जाए। देश में बढ़ती महंगाई के दौर में लोगों को सस्ती और गुणवत्तापरक दवाइयों के जरिए स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। ऐसे में समय आ गया है कि सभी को जेनेरिक दवाओं के माध्यम से सस्ती दवाएं मुहैया कराइ जाएं।

सेवानिवृत्त प्राचार्य शैक्षिक स्तंभकार गली कौर चंद एमएचआर मलोट

भारतीय उच्च शिक्षा में महिलाओं के अग्रणी परिवर्तन

विजय गर्ग

महिला शैक्षणिक नेता और उद्यमी न केवल संस्थानों को आकार दे रहे हैं, बल्कि उनके ग्रिट और दृढ़ संकल्प के साथ भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ाते हैं महिलाएं आज सामने से अग्रणी हैं - शिक्षाविदों या शिक्षा, मीडिया, स्वास्थ्य सेवा, सशस्त्र बलों और कई अन्य क्षेत्रों में। देश एक महत्वपूर्ण बदलाव देख रहा है कि महिला नेताओं को पहले कैसे माना जाता था। भारतीय उच्च शिक्षा परिदृश्य भी एक मजबूत महिला-नेतृत्व वाले बल द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो देश की प्रगति की नींव रखता है, सामाजिक-आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता और जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए अवसरों को अनलॉक करता है। कहने की जरूरत नहीं है, विकसीट भारत की यात्रा में महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा आवश्यक है। शिक्षित महिलाएं परिवर्तन, उत्थान परिवारों, समुदायों को मजबूत करती हैं और राष्ट्रीय प्रगति को ईंधन देती हैं, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी प्रभाव पैदा करती हैं। वर्तमान परिदृश्य और उल्लेखनीय उल्लेख भारतीय उच्च शिक्षा तब पुरुष-प्रधान रहती है जब यह नेतृत्व की बात आती है, यहां तक कि महिलाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, डेटा बताते हैं। 2021 में, महिलाओं ने भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों के सिर्फ 9.55 प्रतिशत का नेतृत्व किया, जबकि पुरुषों ने 89.57 प्रतिशत का नेतृत्व किया। यह अकादमिक नेतृत्व में महिलाओं के अधिक समावेशी प्रतिनिधित्व को बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ भारत की तुलना करते हैं, तो इसे भरने के लिए अभी भी एक बड़ा अंतर है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में 25 प्रतिशत नेतृत्व के पदों पर महिलाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अच्छी खबर यह है कि तस्वीर काफी बदल रही है, खासकर पिछले कुछ वर्षों में। यहां तक कि अतीत में, देश ने एक अग्रणी समाज सुधारक, सावित्रिबाई फुले जैसे दूरदर्शी महिला नेताओं को देखा है, जिन्होंने अपने पति ज्योतिरो फुले के साथ, 1848 में लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूल की स्थापना की, जिसमें महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक न्याय की चैंपियन थे। अन्य उल्लेखनीय और व्यावहारिक महिला नेता जो उच्च शिक्षा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित कर रहे हैं, उनमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के सुश्री रश्मि मित्तल, प्रो-चांसलर और नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के डॉ। उमा भारद्वाज, वाइस-चांसलर शामिल हैं। अन्य सम्मानजनक उल्लेखों में डॉ। मधु चितकारा, चितकारा विश्वविद्यालय में समर्थक चांसलर और 42 साल के एक विशाल अनुभव के साथ एक उच्च शिक्षा उद्यमी शामिल हैं, जिन्होंने खरोंच से एक सफल विश्वविद्यालय का निर्माण किया है; डॉ। अनन्या मुखर्जी, शिव नादर विश्वविद्यालय, दिल्ली-एनसीआर के कुलपति, एक संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त। इसके अलावा, व्यवसाय और उद्यमशीलता के अंतरिक्ष में महिला नेताओं ने भी भारतीय युवाओं को प्रेरित किया है। उल्लेखनीय उल्लेखों में किरण माजुमदार शॉ और इंद्र नूयोई शामिल हैं। महिला नेता समावेशी वातावरण और नवाचार के माध्यम से भारतीय उच्च शिक्षा को बदल रही हैं। नेतृत्व की स्थिति में अधिक महिलाएं विविधता बढ़ाती हैं और शिक्षाविदों में नए दृष्टिकोण लाती हैं। अपने प्रयासों के माध्यम से, वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भारत में अधिक प्रगतिशील और न्यायसंगत शैक्षिक परिदृश्य के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अकादमिया में महिला नेताओं द्वारा सामना की गई चुनौतियां महिला नेताओं के लिए चुनौतियों में एक छोर पर सामाजिक रूढ़िवादिता और दूसरे में एक संस्था की बाधाएं शामिल हैं। कई महिलाएं अभी भी नेताओं के रूप में, विशेष रूप से पारंपरिक क्षेत्रों में अपनी क्षमता के बारे में उनके खिलाफ गंभीर पूर्वाग्रहों का सामना कर रही हैं। महिलाओं को अपने पेशेवर उन्नति के लिए संरक्षक और नेटवर्क प्राप्त करने के अवसरों की

कमी होती है। दुनिया भर में महिला नेताओं के लिए मुख्य मुद्दे काम-जीवन संतुलन और वरिष्ठ नेतृत्व के पदों में अपर्याप्त उपस्थिति से संबंधित हैं। भारतविश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के माध्यम से देश भर में महिला संकाय को ओरिएंट और प्रशिक्षित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण लिया है। इन पहलों को महिलाओं को नेतृत्व भूमिकाओं के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उन्हें सही कौशल और ज्ञान से लैस करते हैं। अन्य देशों में ऐसे कार्यक्रम हैं जो नेतृत्व प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और शिक्षाविदों में महिलाओं के लिए बाधाओं को तोड़ने के लिए समावेशिता। कुछ देशों ने शिक्षाविदों में प्रतिनिधित्व की गई महिलाओं की संख्या में प्रभावशाली वृद्धि देखी है, लेकिन दुनिया को अभी भी भारत सहित एक लंबा रास्ता तय करना है। शिक्षक और नेताओं के रूप में महिलाएं शिक्षा में सशक्तिकरण केवल पहुंच का प्रश्न नहीं है; इसमें महिलाओं को शिक्षकों, नेताओं और मॉडलों की भूमिका से लैस करना शामिल है। स्कूलों और कॉलेजों में महिलाओं की बढ़ती संख्या ने लड़कियों के लिए शिक्षाविदों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एक प्रेरक बल के रूप में काम किया है। उच्च शिक्षा नेतृत्व संस्थानों में महिलाओं के बीच विविध दृष्टिकोण एक समावेशी और अभिनव वातावरण बनाते हैं। महिला प्रोफेसरों ने प्रगतिशील शैक्षिक नीति और अनुसंधान गुणवत्ता के लिए बैकबोन का गठन किया है। कई महत्वपूर्ण विभागों और महत्वपूर्ण अनुसंधान पहलों में अब महिलाएं उन्हें चला रही हैं, विश्वविद्यालय के जीवन में उनके प्रभाव के प्रभाव का सबूत है। लड़कियों और महिलाओं के लिए अवसर प्रदान करने के लिए समर्पित कार्यक्रम और फैलोशिप, विशेष रूप से इन एसटीईएम क्षेत्रों में, इन विषयों के भीतर रचनात्मकता और उत्कृष्टता की संस्कृति की संस्कृति में मदद की है। वर्तमान में, भारत के कुछ सबसे हाई-प्रोफाइल विश्वविद्यालयों और संस्थान हैं, जिसमें महिलाओं के साथ, शिक्षा को और अधिक सुलभ और न्यायसंगत बनाने की प्रवृत्ति की अगुवाई की गई है। महिला नेता शिक्षाविदों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं के नेतृत्व वाली संस्थाएं, प्रतिस्पर्धी परीक्षा कोचिंग संस्थानों की तरह, अपनी आकांक्षाओं को आकार देने में हजारों छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि महिला नेता शिक्षा में परिवर्तनकारी परिवर्तन ला सकते हैं और महान परिवर्तन प्रबंधक हो सकते हैं। उत्प्रेरक या परिवर्तन के एजेंट के रूप में महिलाएं महिलाएं शिक्षक और परिवर्तन के एजेंट हैं। वे इनोवेटर हैं जो ज्ञान अंतराल को भरने, समावेश को बढ़ावा देने और समुदायों को सशक्त बनाने में अच्छे नेता हैं। एक जबरदस्त, समाधान-केंद्रित और उत्तरदायी कार्यबल में उनका योगदान विशेष रूप से इस सरल कारण के लिए अपरिहार्य है कि यह न केवल आर्थिक समृद्धि बल्कि सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित करना है। शिक्षा में महिलाओं का सबसे गहरा-गहरा प्रभाव वयस्क साक्षरता और कौशल विकास में रहा है। महिला शिक्षकों ने ग्रामीण और हाशिए के समुदायों की साक्षरता दर को बढ़ाने की प्रक्रिया का नेतृत्व किया है, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में बहुत सुधार हुआ है। महिला उद्यमी भी भारत भर में विविध शिक्षार्थियों के लिए अभिनव समाधान के साथ आकर शिक्षा वितरण में क्रांति ला रही हैं। महिला संस्थापकों के एडटेक प्लेटफार्मों ने लचीले मॉडल, डिजिटल क्लासरूम एप्लिकेशन और एआई-आधारित एनालिटिक्स को उनके परिचय के साथ बढ़ावा दिया है; इस प्रकार, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के छात्रों के प्रदर्शन को बढ़ाया जाता है क्योंकि अधिक तक पहुंच भी आसानी से संभव हो जाती है। सामाजिक विकास और तकनीकी क्रांति यहां एक दूसरे का समर्थन कर रही है। उच्च शिक्षा में महिलाओं के नेतृत्व का भविष्य उच्च शिक्षा में महिला नेताओं की संख्या में वृद्धि केवल लैंगिक समानता के बारे में नहीं है; यह भारत की प्रगति के लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता है। उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला नेता विभिन्न दृष्टिकोणों और परिवर्तनकारी निर्णय लेने में अकादमिक प्रशासन में लाती हैं, जो इनोवेटो को ड्राइव करती हैn और उत्कृष्टता। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 ने लैंगिक समावेश को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षाविदों में महिलाओं की भागीदारी के महत्व को मान्यता दी है और इस प्रकार प्रस्तावित सुधारों को प्रस्तावित किया है। उच्च शिक्षा के ढांचे के तहत नेतृत्व प्रशिक्षण के समावेश और मेंटरशिप के अवसरों की शुरुआत के माध्यम से, भारत महिला शैक्षणिक नेताओं की एक इष्टतम पाइपलाइन में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा, विकीत भारत और आत्मनिरभर भारत की दृष्टि भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को अवशोषित करने की बहुत आवश्यकता के अनुरूप है। शिक्षा इस दृष्टि के दिल में है, और महिलाओं को शिक्षकों और नेताओं के रूप में सशक्त बनाना भारत की विश्वगुरु बनने की आकांक्षा को साकार करने में महत्वपूर्ण होगा - यानी, जो कि नवाचार और ज्ञान में एक वैश्विक नेता है। निष्कर्ष महिला नेता भारतीय उच्च शिक्षा के भविष्य को निर्विवाद रूप से आकार दे रहे हैं। सभी मौजूदा चुनौतियों के बावजूद, उनकी उत्कृष्टता वर्तमान शिक्षाविदों के भीतर असंख्य सकारात्मक परिवर्तन ला रही है, जो एक अधिक समावेशी, प्रगतिशील और अभिनव शैक्षिक परिदृश्य को जन्म देगा। भारतीय शिक्षा और भारत के सामाजिक-आर्थिक उदारीकरण का समग्र परिवर्तन नेतृत्व के लिए सभी बाधाओं को हटाकर, सहायक नीतियों को लागू करने और उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी को चैंपियन बनाकर प्राप्त किया जा सकता है

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार मलोट पंजाब

प्रोसेस्ड, फास्ट फूड के सेवन से पनपती स्वास्थ्य समस्याएँ

डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत की खाद्य संस्कृति वैश्वीकरण, शहरीकरण और बदलती जीवनशैली के परिणामस्वरूप बदल रही है, जो प्रमुख सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का कारण बन रही है। भारत में युवा पीढ़ी तेजी से फास्ट फूड का सेवन कर रही है, जिसके कारण कई स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा हो रही है, जैसे मोटापा, टाइप 2 मधुमेह और हृदय सम्बंधी विकार। फास्ट फूड में अक्सर बड़ी मात्रा में कैलोरी, चीनी, सोडियम और खराब वसा होती है, जो खराब खाने की आदतों और पोषण सम्बंधी कमियों को जन्म दे सकती है। इसका परिणाम एक गतिहीन जीवन शैली भी हो सकता है, जो किसी के स्वास्थ्य के लिए जोखिम बढ़ाएगा। इस प्रवृत्ति में समय के साथ स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर दबाव डालने और पीढ़ियों के जीवन की सामान्य गुणवत्ता को प्रभावित करने की क्षमता है। क्योंकि यह मोटापे, खराब पोषण और अस्वास्थ्यकर खाने के पैटर्न को बढ़ावा देता है, फास्ट फूड का सेवन बच्चों के स्वास्थ्य और खाने की आदतों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। फास्ट फूड, जिसमें कैलोरी, चीनी और खराब वसा अधिक होती है, मधुमेह और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों के विकास के जोखिम को बढ़ाता है और वज़न बढ़ाता है। फास्ट फूड के लगातार सेवन से बच्चे स्वस्थ खाद्य पदार्थों की तुलना में प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे संतुलित आहार खाने और पौष्टिक भोजन चुनने की उनकी संभावना कम हो जाती है। आजकल, बहुत से युवा फास्ट फूड को पसंद करते हैं क्योंकि यह सुविधाजनक, स्वादिष्ट और जल्दी बनने वाला होता है। इसके नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जानते हुए भी वे इसे खाना जारी रखते हैं। व्यस्त जीवन शैली में, फास्ट फूड को जल्दी से जल्दी खाना सुविधाजनक है। वे भीड़ का अनुसरण करते हैं क्योंकि उनके दोस्त भी इसे पसंद कर सकते हैं।

फास्ट फूड रेस्तरां अपने भोजन में स्वाद और सुगंध भी मिलाते हैं, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट और लगभग नशे की लत बन जाता है। इसके अस्वास्थ्यकर तत्वों, जैसे अत्यधिक वसा और चीनी के बारे में जानने के बाद भी, उन्हें फास्ट फूड की लालसा का विरोध करना मुश्किल लगता है। फास्ट फूड कंपनियाँ अपने उत्पादों को कूल और मनोरंजक दिखाने के लिए भ्रामक विज्ञापन का उपयोग करती हैं, जो एक और कारक है। मशहूर हस्तियों और यादगार नारों का उपयोग ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है, खासकर युवा लोगों का। अपनी बुद्धिमत्ता और शिक्षा के बावजूद, लोग कभी-कभी अपने स्वास्थ्य पर संभावित हानिकारक प्रभावों पर विचार करने के बजाय फास्ट फूड खाने को प्राथमिकता देते हैं। वे ऐसे पेश आते हैं जैसे उन्हें पता है कि यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी वे इसे चुनते हैं क्योंकि यह बहुत सरल और आकर्षक है। इसलिए, बहुत से लोग अभी भी ख़ुद को फास्ट फूड की ओर आकर्षित पाते हैं, भले ही वे इनका नुकसान जानते हों। चूँकि लोग घर के बने खाने की जगह सुविधाजनक भोजन चुन रहे हैं, इसलिए खान-पान की आदतें बदल रही हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में युवा लोग ज़्यादा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। बाजरा जैसे पारंपरिक अनाज की जगह रिफ़ाइंड अनाज और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ ले रहे हैं। बाजरा की खपत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष की शुरुआत की थी। प्रोसेस्ड, उच्च वसा, उच्च चीनी वाले पश्चिमी आहार की बढ़ती संख्या पारंपरिक संतुलित भोजन की जगह ले रही है। मैकडॉनल्ड्स, केएफसी और डोमिनोज़ के तेज़ी से बढ़ने के कारण भारत में शहरी खान-पान की आदतें बदल गई हैं।

वैश्वीकरण के कारण खाद्य संस्कृति के एकरूपीकरण के कारण, क्षेत्रीय व्यंजन अपनी विशिष्टता खो रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में किण्वन-आधारित आहार और अन्य पारंपरिक खाना पकाने की तकनीकें लोकप्रिय नहीं हो रही हैं। खान-पान की बदलती आदतों के कारण, त्योहारों और धर्मों की पाक परंपराएँ अपना महत्त्व खो रही हैं। आयुर्वेदिक और सात्विक आहार जो हिंदू रीति-रिवाजों का एक प्रमुख हिस्सा हैं, उनकी जगह आधुनिक आहार ले रहे हैं। पारंपरिक खान-पान की प्रथाएँ, पारिवारिक भोजन और सामाजिक बंधन सभी फास्ट-फ़ूड संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। अकेले खाने और स्विगी और ज़ोमैटो जैसी ऑनलाइन भोजन वितरण सेवाओं के बढ़ने के परिणामस्वरूप लोगों के साथ मिलकर खाने का तरीक़ा बदल गया है। वैश्विक खाद्य श्रृंखलाओं के परिणामस्वरूप स्ट्रीट वेंडर और स्वदेशी खाद्य कारीगर चुनौतियों का सामना करते हैं। यूनेस्को ने मुंबई की स्ट्रीट फ़ूड संस्कृति को स्वीकार किया है, लेकिन शहरी आधुनिकीकरण इसे खतरे में डाल रहा है। कुपोषण और स्वास्थ्य प्रभावः अधिक प्रसंस्कृत भोजन खाने के परिणामस्वरूप, हृदय रोग, मधुमेह और मोटापे में वृद्धि हुई है। आहार सम्बंधी आदतों में बदलाव के कारण भारत में 101 मिलियन मधुमेह रोगी हो गए हैं। खपत के पैटर्न में बदलाव के कारण पारंपरिक फसलों की मांग में कमी आई है, जिसका असर किसानों के मुनाफे पर पड़ा है। नीति आयोग (2022) के अनुसार, ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए फ़सल विविधीकरण महत्त्वपूर्ण है। छोटे पैमाने के खाद्य व्यवसाय, पारंपरिक भोजनालय और पड़ोस के खाद्य विक्रेता सभी वैश्विक खाद्य श्रृंखलाओं से प्रभावित हैं।

2017 के खाद्य लाइसेंसिंग विनियमों के कारण, छोटे, पारंपरिक रेस्तरां को बंद करना पड़ा। फ़ार्म-टू-टेबल कार्यक्रम और जैविक खेती के प्रति-आंदोलन आकार लेने लगे हैं। भारतीय खाद्य उत्पादों को जैविक भारत पहल द्वारा प्रमाणित जैविक होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्थानीय खाद्य सामर्थ्य वैश्विक खाद्य प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है जो आयात पर निर्भरता बढ़ाते हैं। गेहूँ और पाम ऑयल के लिए आयात लागत में वृद्धि का घरेलू खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। अपनी नींव को बनाए रखते हुए, भारत की विविध पाक संस्कृति को बदलना होगा। टिकाऊ खाद्य नीतियों, देशी फसलों के समर्थन और संतुलित आहार जागरूकता के कार्यान्वयन के माध्यम से आधुनिकीकरण द्वारा पारंपरिक खाद्य विविधता और सांस्कृतिक पहचान को कम करने के बजाय बढ़ाया जा सकता है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कभी-कभार फास्ट फूड खाने से आपके सामान्य स्वास्थ्य पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। दूसरी ओर, नियमित रूप से फास्ट फूड खाने से अंततः कई स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं। अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सीमित करना लक्ष्य है।

छात्रों द्वारा स्मार्टफोन का बेतहाशा इस्तेमाल चिंताजनक

विजय गर्ग

इस समय पूरे देश में स्कूली छात्रों द्वारा मोबाइल का गैर-जरूरी इस्तेमाल सामाजिक चिंताओं को जन्म दे रहा है। देश में 21 राज्यों के ग्रामीण समुदायों में 6-16 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों के 6,229 अभिभावकों के बीच किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि अधिकतर बच्चे पढ़ाई की बजाय मनोरंजन एवं अश्लील सामग्री के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। शोध एवं अध्ययनों में पाया गया है कि जो छात्र अपने फोन के करीब रहकर पढ़ाई करते हैं, उन्हें ध्यान केंद्रित करने में बहुत मुश्किल होती है, भले ही वे उसका इस्तेमाल न कर रहे हों। स्मार्टफोन के इस्तेमाल से नींद की गुणवत्ता कम होने, तनाव बढने, एकाग्रता बाधित होने, स्मृति लोप होने, अवांछित सामग्री का अधिक इस्तेमाल करने, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पडने जैसे खतरे उभरे हैं।

इन बढ़ते खतरों को देखते हुए दुनियाभर में अनेक शिक्षा प्रणालियों ने स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी (जी.ई.एम.) टीम के अनुसार, 60 शिक्षा प्रणालियों या वैश्विक स्तर पर पंजीकृत कुल शिक्षा प्रणालियों में से 30 प्रतिशत ने विशेष कानूनों या नीतियों के माध्यम से 2023 के अंत तक स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया था। डिजिटल शिक्षा और स्मार्टफोन के इस्तेमाल में बच्चों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। यह कोई बुरी बात नहीं है। यह बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहा है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी हैं, जिनमें डिजिटल शिक्षा को संतुलित और सुरक्षित बनाना आने वाले समय में एक प्रमुख चुनौती है। डिजिटल शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के साथ आवश्यक हो गया है कि स्मार्टफोन और इंटरनैट का सही, संयमपूर्ण और सुरक्षित इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए।

सर्वविदित है कि विभिन्न ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रमों के चलते छात्र-छात्राओं में मोबाइल फोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। तमाम पब्लिक स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा के

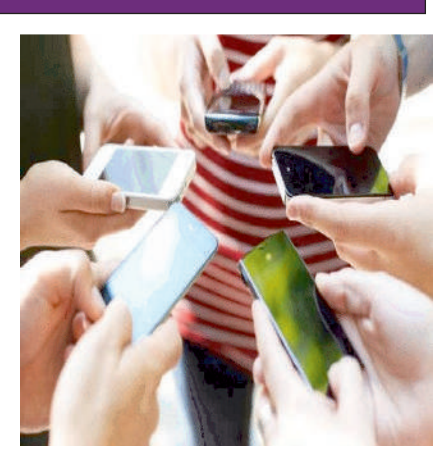

लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल अनिवार्य तक बना दिया है। कमोबेश सरकारी स्कूलों में ऐसी बाध्यता नहीं है। लेकिन वैश्विक स्तर पर किए गए सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि स्मार्टफोन एक हद तक तो सीखने की प्रक्रिया में मददगार साबित हुआ है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।आज 60 प्रतिशत माता-पिता अपने बच्चों द्वारा टैक्नोलॉजी के इस्तेमाल की निगरानी नहीं करते और 75 प्रतिशत बच्चों को उनके बैडरूम में टैक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की खुली छूट मिली है।आज लाखों की संख्या में 9-10 साल की उम्र के इन बच्चों की नींद और स्टडीज टैक्नोलॉजी के दखल के कारण प्रभावित हो रही हैं।

स्मार्टफोन के अनियंत्रित इस्तेमाल से बच्चों में डिप्रैशन, एंग्जाइटी, अटैचमैंट डिस्ऑर्डर, ध्यान नहीं लगना, बाइपोलर डिस्ऑर्डर, उन्माद और प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड बिहेवियर जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इससे पैदा होने वाली सभी प्रकार की समस्याओं पर स्कूल शिक्षा से जुड़े सभी लोगों का संजीदा होना आवश्यक लग रहा है और इसके लिए, सभी निहित कदम उठाना सामयिक जरूरत है।

सेवानिवृत्त प्राचार्य शैक्षिक स्तंभकार गली कौर चंद एमएचआर मलोट

एआई अपनाने पर भारतीय कंपनियों का जोर, लेकिन यहां हो रही दिक्कत

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में AI तेजी से बिजनेस रणनीति बन रहा है लेकिन योग्य प्रोफेशनल्स की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है। लिंक्डइन रिपोर्ट के अनुसार 54% HR प्रोफेशनल्स को उपयुक्त कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं। टेक्निकल AI स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स की मांग बढ़ रही है। कंपनियां सेलेक्टिव हायरिंग और अपस्किलिंग पर जोर दे रही हैं। 48% बिजनेस लीडर्स AI ट्रेनिंग को महत्वपूर्ण मानते हैं।

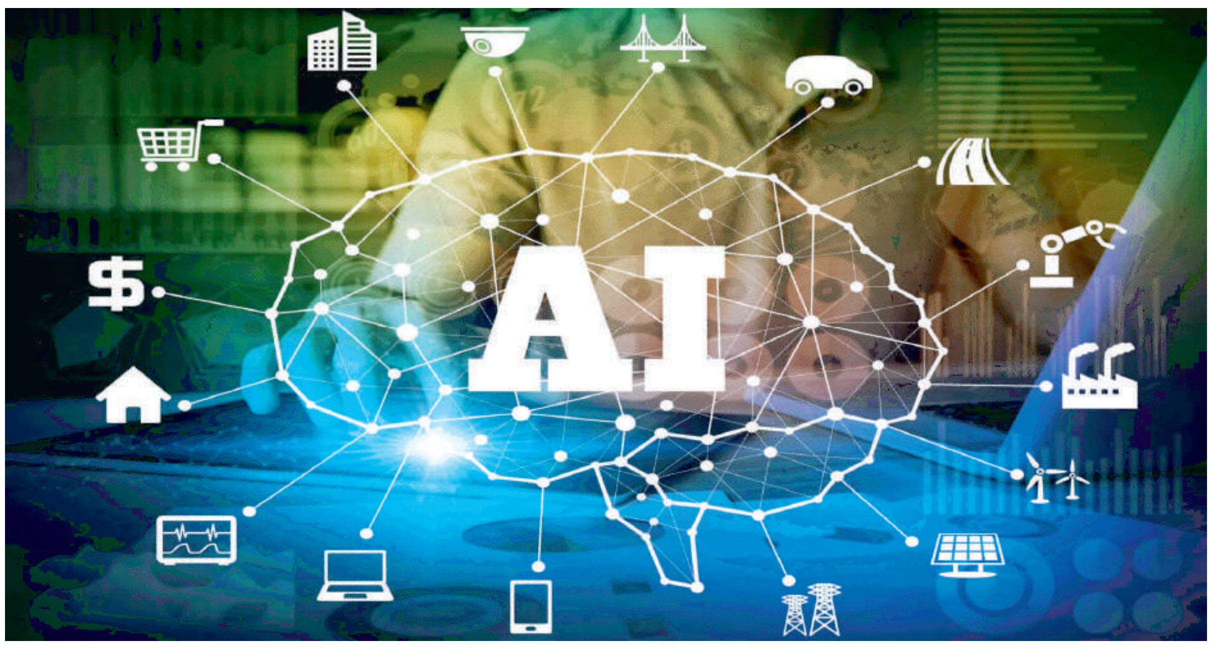

नई दिल्ली। भारत में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब सिर्फ चर्चा का विषय नहीं रहा। यह जरूरी बिजनेस स्ट्रैटजी बन चुका है। भारतीय कंपनियों के अधिकतर एग्जीक्यूटिव्स AI को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस तकनीक की पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए योग्य प्रोफेशनल्स की भारी कमी है।

लिंक्डइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ₹भारत में 54% HR प्रोफेशनल्स का कहना है कि उन्हें मिलने वाले जॉब एप्लिकेशन्स में से केवल आधे या उससे कम ही सभी जरूरी योग्यताओं पर खरे उतरते हैं। इसके अलावा वे ₹तकनीकी स्किल्स (61%) और सॉफ्ट स्किल्स (57%) की कमी₹ को सबसे बड़ी हायरिंग चुनौती मानते हैं।

भारत में सबसे मुश्किल से मिलने वाली स्किल्स

टेक्निकल/आईटी स्किल्स जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग (44%)

AI स्किल्स (34%)

सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम-सॉल्विंग (33%)

इस स्किल गैप के चलते कंपनियां अब हायरिंग प्रोसेस में ज्यादा सेलेक्टिव (Selective Hiring) हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में भारत में आधे से ज्यादा HR प्रोफेशनल्स (55%) केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को तवज्जो देने पर विचार कर रहे हैं, जो 80% या उससे अधिक जॉब क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं।

AI को अपनाने के लिए जरूरी है सही टैलेंट

भारत लिंक्डइन का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है, जहां प्लेटफॉर्म के 150 मिलियन से अधिक मेंबर्स हैं और हर साल इसमें 20% की बढ़ोतरी हो रही है।

लिंक्डइन की इंडिया टैलेंट एंड लर्निंग सॉल्यूशंस हेड रुचि आनंद के मुताबिक, ₹AI अपनाना ही सफलता की कुंजी नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से बिजनेस में लागू करना सबसे अहम है।₹ उन्होंने कहा, ₹कई कंपनियां AI टूल्स में भारी निवेश करती हैं, लेकिन बिना सही टैलेंट के वे इनका पूरा फायदा नहीं उठा पातीं, जिससे यह गेम-चेंजर अवसर मिस हो जाता है।₹

भारतीय कंपनियों का अपस्किलिंग पर जोर

इस स्किल गैप को दूर करने के लिए भारतीय कंपनियां अपने कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्किल डेवेलपमेंट पर फोकस कर रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि 48% भारतीय बिजनेस लीडर्स मानते हैं कि AI ट्रेनिंग में निवेश करना इसकी तेजी से अपनाने की कुंजी होगा।

इस रिपोर्ट को लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के डेटा और वैश्विक सर्वे के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें 1,991 C-सूट एग्जीक्यूटिव्स और 300 से अधिक चीफ HR ऑफिसर्स शामिल थे, जो 1,000+ कर्मचारियों वाली कंपनियों में काम कर रहे हैं।

पेटीएम की सरकार के साथ हुई डील, क्या शेयरों में दिखेगी हलचल?

सरकार ने Paytm के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत स्टार्टअप्स को मेंटरशिप बाजार पहुंच और फंडिंग के अवसर मिलेंगे। यह साझेदारी फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स के विकास में तेजी लाएगी। Paytm for Startups पहल में निवेश नियामक मार्गदर्शन और वर्कशॉप शामिल हैं। पेटीएम के शेयरों में हालिया उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। आइए जानते हैं पूरी खबर।

नई दिल्ली। सरकार ने Paytm (One97 Communications Ltd) के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत कंपनी स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, बाजार तक पहुंच और फंडिंग के अवसर प्रदान करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने Paytm के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मकसद देश में विनिर्माण और फिनटेक स्टार्टअप्स के नवाचार को बढ़ावा देना और उनके विकास में तेजी लाना है। इस MoU पर DPIIT के निदेशक सुमीत कुमार जरंगल और Paytm के फाउंडर एवं सीईओ विजय शेखर शर्मा ने हस्ताक्षर किए।

साझेदारी पर क्या बोले पेटीएम और सरकार

मंत्रालय ने कहा, ₹इस साझेदारी के तहत, Paytm स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, बाजार पहुंच और फंडिंग के मौके देगा। जिससे वे अपने व्यवसाय को तेजी से बढ़ा सकें और इनोवेशन कर सकें।₹ यह पहल उद्यमियों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने में मदद करेगी। इससे वे अत्याधुनिक भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी समाधान विकसित कर सकें। वे Paytm के बड़े व्यापारी नेटवर्क का लाभ भी उठा सकेंगे।

DPIIT के संयुक्त सचिव संजीव ने कहा, ₹Paytm की फिनटेक विशेषज्ञता और इन्फ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाकर, हम उद्यमियों को चुनौतियों से उबरने और अपने वेंचर को बढ़ाने में सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं।₹ वहीं, Paytm के संस्थापक एवं सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कहा, ₹Paytm उद्यमियों को मेंटरशिप, वित्तीय सहायता और अत्याधुनिक तकनीक तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।₹

Paytm for Startups पहल में क्या होगा?

कंपनी फिनटेक हार्डवेयर निर्माताओं को समर्थन देने के लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम शुरू करेगी। ये पहल मेंटरशिप कार्यक्रम, निवेशकों के साथ फंडिंग के अवसर, नियामक मार्गदर्शन, इंडस्ट्री-फोकस्ड वर्कशॉप और प्रभाव आकलन शामिल करेंगी। DPIIT इससे पहले Apna (प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म), Rukam Capital, Avaana Capital, Bhaane Group, Flipkart और ITC जैसी कई कंपनियों के साथ इसी तरह के समझौते कर चुका है।

पेटीएम के शेयरों का हाल क्या है?

पेटीएम के शेयर मंगलवार को 2.81 फीसदी की गिरावट के साथ 733.90 रुपये पर बंद हुए थे। पिछले 6 महीने के दौरान इसमें 38.37 फीसदी की तेजी आई है। वहीं, बीते एक साल में इसने 71 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया है। हालांकि, पेटीएम अभी भी अपने आईपीओ प्राइस के मुकाबले काफी नीचे है। अगर लिस्टिंग के बाद से देखा जाए, तो पेटीएम के शेयरों ने अभी तक 52.98 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पेटीएम का मार्केट कैप 46.80 हजार करोड़ रुपये है।

यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी; रोजगार की नहीं होगी शर्त, सबको मिलेगा फायदा

सरकार Universal Pension Scheme लाने पर विचार कर रही है जो स्वैच्छिक और अंशदायी होगी। इस योजना में रोजगार की अनिवार्यता नहीं होगी जिससे असंगठित क्षेत्र के मजदूर छोटे व्यापारी और स्वरोजगार करने वाले लोग पेंशन लाभ उठा सकेंगे। यह योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-Traders) जैसी मौजूदा योजनाओं को एकीकृत कर सकती है जिससे सामाजिक सुरक्षा (Social Security) को मजबूत किया जाएगा।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने पर विचार कर रही है। यह स्वैच्छिक (Voluntary) और अंशदायी (Contributory) होगी। इस पेंशन योजना के लिए रोजगार कोई शर्त नहीं होगी यानी इसमें आम नागरिक भी योगदान कर सकेंगे और फिर पेंशन पा सकेंगे। इस योजना का मकसद पारंपरिक रोजगार से परे सामाजिक सुरक्षा (Social Security) का विस्तार करना है। NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस प्रस्तावित समग्र योजना (Umbrella Scheme) पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है, जो मौजूदा पेंशन योजनाओं (Pension Schemes) को एकीकृत करने की दिशा में बढ़ेगी।

यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में क्या होगा?

इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत बनाया जा रहा है। इसके अंतिम प्रारूप को तैयार करने के बाद अलग-अलग हितधारकों (Stakeholders) की राय ली जाएगी।

नई योजना स्वैच्छिक होगी, यानी कोई भी इसमें शामिल हो सकेगा, चाहे उसके पास कोई नौकरी हो या नहीं।

इससे असंगठित क्षेत्र के लोग, जैसे कि छोटे व्यापारी, स्वरोजगार करने वाले भी योजना में शामिल हो सकेंगे।

इसमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS-Traders) जैसी मौजूदा पेंशन योजनाओं को मर्ज किया जा सकता है।

ये योजनाएं रिटायरमेंट के बाद ₹3,000 की मासिक पेंशन प्रदान करती हैं, जिसमें ₹55 से ₹200 तक का योगदान किया जाता है, और सरकार भी इसमें बराबर का योगदान देती है।

अटल पेंशन योजना (APY) को भी इस नए ढांचे में शामिल करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है।

सरकार Building and Other Construction Workers (BoCW) Act के तहत लिए गए उपकर (Cess) को निर्माण श्रमिकों की पेंशन वित्तीय सहायता के लिए उपयोग करने पर भी विचार कर रही है।

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

यह योजना खासकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार करने वालों और अन्य नागरिकों के लिए बनाई जा रही है। इसमें 18 साल या उससे अधिक उम्र के वे लोग शामिल हो सकेंगे, जो 60 साल के बाद पेंशन लाभ (Pension Benefits) पाना चाहते हैं।

केंद्र सरकार राज्यों को भी इस योजना में अपनी पेंशन योजनाओं को विलय करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इससे पेंशन अंशदान को एक जगह लाया जा सकेगा। इससे पेंशन भुगतान (Pension Payout) में वृद्धि होगी। साथ ही, एक शख्स को अधिक पेंशन का लाभ लेने से भी रोका जा सकेगा।

भारत में वृद्ध आबादी का बढ़ता दबाव

मौजूदा अनुमानों के अनुसार, 2036 तक भारत में वरिष्ठ नागरिकों (60 साल और उससे अधिक) की संख्या 22.7 करोड़ तक पहुंच सकती है।

डब्ल्यूटीओ पड़ रहा कमजोर... वित्त मंत्री ने क्यों कही ये बात, क्या है भारत का नया ट्रेड प्लान

परिवहन विशेष न्यूज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को व्यापार और निवेश के लिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना होगा क्योंकि बहुपक्षीय संस्थान कमजोर हो रहे हैं। वैश्विक व्यापार का पुनर्गठन हो रहा है और WTO का प्रभाव घट रहा है। भारत ने यूके अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं शुरू की हैं। सरकार वित्तीय अनुशासन और ऋण प्रबंधन पर ध्यान दे रही है।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि भारत को व्यापार और निवेश के लिए अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में बड़े बदलाव हो रहे हैं और द्विपक्षीय सहयोग अब एक नया प्रभावी तरीका बनता जा रहा है। उन्होंने गुरुवार को BS Manthan कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि ये समय दिलचस्प लेकिन चुनौतीपूर्ण हैं और सरकार भारत को वैश्विक वृद्धि का एक प्रमुख इंजन बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है।

वित्त मंत्री ने कहा, ₹द्विपक्षीय सहयोग अब प्रमुख एजेंडे में शामिल हो रहा है... हमें व्यापार और निवेश के अलावा रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कई देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना होगा। बहुपक्षीय सहयोग (Multilateralism) अब धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है। हालांकि, मैं इसे पूरी तरह खत्म नहीं कहूंगी, लेकिन द्विपक्षीय सहयोग ही वह प्रभावी तरीका है, जिसका उपयोग किया जा सकता है।"

बहुपक्षीय संस्थाओं की घटती भूमिका

निर्मला सीतारमण ने कहा कि बहुपक्षीय संस्थान (Multilateral Institutions) धीरे-धीरे बेअसर होते जा रहे हैं। उन्हें रिवाइव करने की कोशिश से भी मनचाहा नतीजा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, ₹ऐसे मुद्दे जिनका प्रभाव सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, उन्हें हल करने के लिए अब कोई प्रभावी मंच नहीं बचा है... बहुपक्षीय संस्थानों का योगदान धीरे-धीरे घटता जा रहा है। कम से कम निकट भविष्य में इन्हें प्रभावी बनाने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है।₹

वैश्विक व्यापार में बदलाव और WTO की कमजोर स्थिति

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि वैश्विक व्यापार पूरी तरह से पुनर्गठित (Reset) हो रहा है। उन्होंने कहा, ₹जिस ढांचे और नियमों के तहत हम अब तक व्यापार कर रहे थे, विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तहत, वे अब प्रभावी नहीं रहे।₹

उन्होंने कहा कि ₹Most Favoured Nation (MFN)₹ का कॉन्सेप्ट पर प्रासंगिक नहीं रहा। हरेक देश चाहता है कि उसे विशेष दर्जा मिले और यह तय किया जाए कि यह दर्जा अपनेआप न मिले, बल्कि उसके रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए मिले। अगर WTO कमजोर हो रहा है और बहुपक्षीय संस्थान प्रभावी नहीं हैं, तो व्यापार के मामले में द्विपक्षीय समझौते अब प्राथमिकता बन जाएंगे।"

भारत के द्विपक्षीय व्यापार वार्ता और समझौते

भारत ने इस नए वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं शुरू कर दी हैं। भारत यूरोपीय संघ (EU) के 27 देशों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर बातचीत कर रहा है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि ₹नए ग्लोबल ऑर्डर (Global Order) में भारत को व्यापार, निवेश और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना होगा।₹ उन्होंने कहा कि भारत के पास तकनीक और प्रतिभा का एक विशाल भंडार है, जिससे यह वैश्विक वृद्धि का इंजन बन सकता है।

ग्लोबल इकोनॉमिक में भारत की अहम भूमिका

सीतारमण ने कहा, ₹मुझे लगता है कि ये समय बहुत दिलचस्प लेकिन चुनौतीपूर्ण हैं... भारत को वैश्विक पुनर्गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। साथ ही हमें अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधारनी होगी, जिससे भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में आगे बढ़े और एक प्रमुख व्यापार और निवेश केंद्र बने। हमें ऐसा देश बनना होगा जहां प्रतिभा और पूंजी दोनों आसानी से प्रवाहित हो सकें, जिससे हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति दे सकें।"

सुधारों पर सरकार का ध्यान

वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय अनुशासन (Fiscal Prudence) बनाए रखना और ऋण प्रबंधन (Debt Management) सुधारना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। उन्होंने कहा कि सुधार केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि राज्य सरकारों को भी इसे गंभीरता से अपनाना होगा।

उन्होंने कहा, "मैं चाहूंगी कि राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, जहां हर राज्य यह कहे कि उसकी अर्थव्यवस्था अन्य राज्यों से बेहतर है।"

एनबीएफसी और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को अधिक कर्ज दे सकेंगे बैंक, आरबीआई से मिली बड़ी राहत

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (Microfinance Institutions - MFIs) को ऋण देने के लिए बैंकों के जोखिम भारांश (Risk Weight) को कम कर दिया है। इससे बैंकों की ऋण देने की क्षमता (Lending Capacity) बढ़ेगी और छोटे उधारकर्ताओं को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के माइक्रोफाइनेंस लोन पर 100% जोखिम भार लागू रहेगा।

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और सूक्ष्म वित्त (Microfinance) लोन देने वाली इकाइयों को बड़ी राहत दी है। अब बैंक इन कंपनियों को अधिक कर्ज दे सकेंगे, क्योंकि आरबीआई ने उनके लिए बैंक वित्त पर लागू जोखिम भारांश (Risk Weight) को घटा दिया है। इसे बैंक और NBFC के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

क्या है यह बदलाव और इसका असर?

आरबीआई के इस निर्णय से बैंकों की ऋ्रण देने की क्षमता में वृद्धि होगी, क्योंकि उन्हें उपभोक्ता ऋ्रण के लिए सुरक्षा निधि के रूप में कम पूंजी अलग रखनी होगी। इससे उपभोक्ताओं को आसानी से ऋ्रण उपलब्ध हो सकेगा और एनबीएफसी व माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को भी फंडिंग की बेहतर सुविधा मिलेगी।

पिछले साल बढ़ाया गया था जोखिम भारांश

नवंबर 2023 में, आरबीआई ने एनबीएफसी और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के कर्ज देने के मानकों को कड़ा कर दिया था। इसके तहत उन सभी एनबीएफसी के लिए, जिनकी बाहरी क्रेडिट रेटिंग के अनुसार जोखिम भार 100% से कम था, उनके कर्ज पर जोखिम भार 25% तक बढ़ा दिया गया था। इससे बैंकों की मुश्किल बढ़ गई थी। उन्हें कंपनियों को दिए जाने वाले लोन पर अतिरिक्त पूंजी अलग रखने की जरूरत पड़ रही थी, जिससे ऋ्रण प्रवाह प्रभावित हुआ था।

क्षेत्रीय ग्रामीण और स्थानीय बैंकों के लिए नियम

आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन सूक्ष्म वित्त ऋ्रणों को उपभोक्ता कर्ज की श्रेणी में नहीं रखा गया है और जो कुछ नियामकीय मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें नियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो (Regulatory Retail Portfolio - RRP) में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए बैंकों को उचित नीतियां और संचालन प्रक्रियाएं लागू करनी होंगी। इसके अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) और स्थानीय क्षेत्र बैंक (LAB) द्वारा दिए गए माइक्रोफाइनेंस ऋ्रणों पर 100% जोखिम भारांश लागू रहेगा।

RBI के फैसले का क्या होगा असर?

एनबीएफसी और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के लिए ऋ्रण प्रवाह में वृद्धि होगी।

बैंकों को कम पूंजी अलग रखने की जरूरत होगी, जिससे वे अधिक लोन देने में सक्षम होंगे।

छोटे कर्ज लेने वाले व्यवसायों और ग्राहकों को लाभ मिलेगा।

इक्रा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता ने कहा, "इस क्षेत्र में मौजूदा प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए यह एक स्वागतयोग्य कदम है। इससे संबंधित कंपनियों को राहत मिलेगी और ऋ्रण प्रवाह में तेजी आएगी।"

क्रेडिट कार्ड खर्च में उछाल: जनवरी 2025 में 1.84 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन, UPI का दबदबा बरकरार

जनवरी 2025 में क्रेडिट कार्ड खर्च 10.8% बढ़कर 1.84 लाख करोड़ हुआ। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के उपभोक्ताओं ने सबसे अधिक खर्च किया। पांच सालों में क्रेडिट कार्ड की संख्या 10.8 करोड़ हो गई। यूपीआई डिजिटल भुगतान में 83% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है। 2018 से 2024 के बीच यूपीआई लेनदेन 17221 करोड़ तक पहुंच गया जिससे पारंपरिक पेमेंट सिस्टम का यूज घटा है।

नई दिल्ली। भारत में डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ रहा है। जनवरी २०२५ में क्रेडिट कार्ड के जरिए उपभोक्ताओं ने 1.84 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। यह पिछले साल की तुलना में 10.8% अधिक है। हालांकि, डिजिटल पेमेंट के मामले में यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम) का दबदबा बना हुआ है। यह करीब ८३ फीसदी की पसंदीदा ऑनलाइन पेमेंट का तरीका है। आइए क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के चलन का पूरा लेखाजोखा जानते हैं।

HDFC और ICICI बैंक का दबदबा : HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं ने ५०,६६४ करोड़ रुपये खर्च किए, जो १५.९१% की बढ़ोतरी है।

ICICI बैंक के ग्राहकों का खर्च ३५,६८२ करोड़ रुपये रहा, जिसमें २०.२५% की वृद्धि देखी गई।

एसबीआई क्रेडिट कार्ड धारकों ने २८,९७६ करोड़ रुपये खर्च किए, जो पिछले साल की तुलना में ६% कम है।

एक्सिस बैंक के ग्राहकों का खर्च २०,२१२ करोड़ रुपये रहा, जो 0.45% की गिरावट दर्शाता है।

क्रेडिट कार्ड की संख्या में तेज वृद्धि

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, क्रेडिट कार्ड की संख्या पिछले पांच वर्षों में दोगुनी से अधिक बढ़कर 10.8 करोड़ हो गई। एचडीएफसी बैंक ने जनवरी में २,९९,७६१ नए क्रेडिट कार्ड जारी किए। एसबीआई ने २,३४,५३७ नए क्रेडिट कार्ड जोड़े। वहीं, आईसीआईसीआई बैंक ने 1,८३,१५७ नए क्रेडिट कार्ड जारी किए।

आवासीय बाजार में जोरदार तेजी, दिल्ली-एनसीआर में 31 फीसदी बढ़े घरों के दाम

परिवहन विशेष न्यूज

2024 की अंतिम तिमाही में भारत के आठ प्रमुख शहरों में मकानों की कीमतों में 10% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली-एनसीआर (31%) और बेंगलुरु (23%) में सबसे अधिक उछाल आया। बिना बिके मकानों की संख्या घटी खासकर पुणे (14%) और हैदराबाद (13%) में। लग्जरी और अल्ट्रा-लक्जरी सेगमेंट की मांग बढ़ रही है। 2025 में ब्याज दरों में कटौती से बिक्री और बढ़ने की संभावना है।

नई दिल्ली। कैलेंडर ईयर 2024 की अंतिम तिमाही में भारत के आठ प्रमुख शहरों में आवासीय संपत्तियों की औसत कीमतों में 10% सालाना वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि 2021 से लगातार 16वीं तिमाही जारी रही, जो मजबूत मांग और सकारात्मक बाजार रुझानों का संकेत है।

दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु में सबसे तेज ग्रोथ

दिल्ली-एनसीआर में सबसे ज्यादा 31% की वृद्धि हुई, खासकर लग्जरी और अल्ट्रा-लग्जरी सेगमेंट में।

बेंगलुरु में 23% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई।

अहमदाबाद में 15%, पुणे में 9% और चेन्नई में 6% की वृद्धि हुई।

हैदराबाद में मात्र 2% और कोलकाता में 1% की हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

बिना बिके मकानों की संख्या में गिरावट

2024 की चौथी तिमाही में बिना बिके मकानों की संख्या लगातार चौथी बार घटी और सालभर में इसमें 5% की कमी दर्ज की गई। देशभर में बिना बिके मकानों की संख्या दिसंबर 2024 तक पहली बार 10 लाख से कम हो गई।

पुणे में सबसे अधिक 14% और हैदराबाद में 13% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, 40% बिना बिके मकान अकेले मुंबई मेट्रो रीजन (MMR) में थे।

बड़े मकानों और बेहतर सुविधाओं की मांग बढ़ी

क्रेडाई नेशनल के अध्यक्ष बोमन ईरानी के अनुसार, ₹मकानों की कीमतों में बढ़ोतरी यह बताती है कि खरीदारों का भरोसा बना हुआ है। लोग अब बड़े घरों और बेहतर सुविधाओं वाले अपार्टमेंट्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे एकीकृत टाउनशिप और हाई-एंड प्रोजेक्ट्स की मांग बढ़ रही है।₹ उन्होंने यह भी बताया कि निर्माण लागत और ऊंची जमीन की कीमतें भी इस वृद्धि के प्रमुख कारण हैं।

2025 में भी कीमतों में तेजी की संभावना

कोलियर्स इंडिया के CEO बादल याग्निक का कहना है, ₹दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु जैसे शहरों में लग्जरी और अल्ट्रा-लग्जरी सेगमेंट की मांग बढ़ने से कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल आया है।₹ रेपो रेट में कटौती और सरकारी योजनाओं से किफायती मकानों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। अगर ब्याज दरें घटती हैं, तो मकानों की बिक्री तेज होगी और 2025 में भी कीमतों में इसी तरह की 10% सालाना वृद्धि जारी रह सकती है।

देशभर के आईटीआई और एनएसटीआई के लिए बने नए कोर्स, युवाओं की तकनीकी स्किल्स में होगा सुधार, मिलेंगी जॉब

देशभर के ITI और NSTI के लिए नए कोर्स बनाए गए हैं। इससे युवाओं की तकनीकी स्किल्स में सुधार होगा और नई जॉब मिलने की राह आसान हो जाएंगी। युवाओं को नई तकनीकों में कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय ने नए पाठ्यक्रम बनाए हैं। आईटी एआई रोबोटिक्स सेमीकंडक्टर ड्रोन और 5जी तकनीकें रोजगार के अवसर बढ़ाएंगी। प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा सभी राज्यों को इस संबंध में अवगत करा दिया है।

नई दिल्ली। उद्योग जगत यह चिंता जताता रहा है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दिया जा रहा तकनीकी प्रशिक्षण वर्तमान या भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस (एआई) ने इस चुनौती को और भी बढ़ा दिया है। इसे देखते हुए सरकार ने स्किल ईकोसिस्टम के कायाकल्प पर काम तेज कर दिया है।

सिस्टम पर बोझ बन रहीं 5358 आइटीआइ की मान्यता हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने रद की और अब प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने देशभर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ), राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआइ) और प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीओटी) के लिए नए पाठ्यक्रम तैयार किए हैं।

तकनीकी पाठ्यक्रम युवाओं को बना सकेंगे अधिक योग्य

उम्मीद जताई गई है कि आईटी, एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, ड्रोन और 5जी जैसी तकनीक में प्रशिक्षित कर यह पाठ्यक्रम युवाओं को रोजगार के अधिक योग्य बना सकेंगे। प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा सभी राज्यों को इस संबंध में अवगत करा दिया है कि भारत में स्किल डेवलपमेंट ईको सिस्टम को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

पुराने कोर्स को किया गया है रिवाइज

इस प्रक्रिया के तहत ही दीर्घकालिक और लघु अवधि के नए पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ ही कुछ पुराने कोर्स को रिवाइज यानी पुनरीक्षित भी किया गया है। युवाओं को व्यावहारिक तकनीकी प्रशिक्षण भी बेहतर मिल सके, इसलिए 150 घंटों की आनजॉब ट्रेनिंग को अनिवार्य किया गया है। यह सभी नए पाठ्यक्रम क्राफ्टमेन ट्रेनिंग स्कीम (सीटीएस) और क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के तहत चलाए जाएंगे।

31 कोर्स किए जा चुके हैं शामिल

न्यू एज या फ्यूचर स्किल कोर्स श्रेणी में 5जी नेटवर्क टेक्नीशियन, एआइ प्रोग्रामिंग असिसटेंट, साइबर सिक्योरिटी असिसटेंट, ड्रोन पायलट जूनियर जैसे 31 कोर्स शामिल किए जा चुके हैं। अब इसमें सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर का इंडस्ट्रियल इंटरनेट आफ थिंग्स टेक्नीशियन और पर्यावरण विज्ञान क्षेत्र के लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेकनीशियन कोर्स भी जोड़ा गया है।

नए शॉर्ट टर्म कोर्स

फंडामेंटल्स आफ इंटरनेट आफ थिंग्स एप्लीकेशन एंड मेंटिनेंस, फंडामेंटल्स आफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलाजी, बेसिक्स आफ साइबर सिक्योरिटी, बेसिक्स आफ जेनेरेटिव एआई, बेसिक्स आफ आइटी स्किल्स, फंडामेंटल्स आफ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, फंडामेंटल्स आफ सीएनसी प्रोग्रामिंग एंड आपरेशन, फंडामेंटल्स आफ एचवीएसी, इंट्रोडक्शन आफ इंडस्ट्री-4.0, बेसिक्स आफ रिपेयर एंड मेंटिनेंस आफ मेटल कटिंग मशीन।

रिवाइज किए गए कोर्स

वर्चुअल एनालिसिस एंड डिजाइनर (फाइनाइट एलीमेंट मैथड), इंजीनियरिंग डिजाइन टेक्नीशियन, सीएनसी मशीनिंग टेक्नीशियन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (थ्री-डी प्रिंटिंग) टेक्नीशियन, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड आटोमेशन टेक्नीशियन, मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंडस्ट्रियल आटोमोटिव मैन्युफैक्च¨रग टेक्नीशियन और एयरोनाटिकल स्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट फिटर।

नए पाठ्यक्रम युवाओं को सशक्त बनाएंगे

'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय उद्योगों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण को लगातार आधुनिक बना रहा है। नए जमाने के पाठ्यक्रमों की शुरुआत हमारे युवाओं को सशक्त बनाएगी, उन्हें उभरती तकनीकों में दक्ष बनाएगी।'

अतुल कुमार तिवारीसचिव, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

ग़ज़ल : जिन्दगी से अब कोई शिकायत नहीं...!

जिन्दगी से अब कोई शिकायत तो नहीं,
वेतन भले कम मिले 'निहायत' तो नहीं।
ये माना इस जिन्दगी में वो रफ्तार नहीं,
चलने दो इसे इसमें तुम गिरफ्तार नहीं।
ना सोचा करों इसके बारे में बेकार नहीं,
बेफिक्र हो जियों इसे भले स्वीकार नहीं।

जिन्दगी से अब कोई शिकायत तो नहीं,
वेतन भले कम मिले 'निहायत' तो नहीं।
एक सड़क है ये इस पर चलते जाना है,
मंजिल कहाँ हमें उसका पता लगाना है।
इस राह में तुम्हारी यह बेदर्द जमाना है,
कुछ हासिल भले न हो कदम मिलाना है।

जिन्दगी से अब कोई शिकायत तो नहीं,
वेतन भले कम मिले 'निहायत' तो नहीं।
अब चलो स्वयं को 'संतोषी' ही मानकर,
यूँ ही गुजारना हैं जिंदगी स्वाभिमान पर।
आस-पास भले क्यों न हो कांटो भरें रास्ते,
बिन 'पदसेविका' पहने चलों अपने वास्ते।

संजय एम तराणेकर

अमेरिका फर्स्ट या धन फर्स्ट? [नागरिकता का सौदा: अमेरिका की आत्मा दांव पर]

अमेरिका, जो युगों से समता, स्वाधीनता और संभावनाओं का पावन तीर्थ रहा है, आज एक ऐसे संकटमय दोराहे पर खड़ा है, जहां उसके मूलभूत मूल्य और आदर्श संदेह के कटघरे में हैं। डोनाल्ड ट्रंप की यह नई रणनीति—जिसमें 50 लाख डॉलर के निवेश के बदले विदेशी धन-कुबेरों को नागरिकता का स्वर्णिम पासपोर्ट थमाया जा रहा है—महज एक आर्थिक कदम नहीं, बल्कि उस सामाजिक ढांचे पर करारा आघात है, जो अमेरिका की आत्मा का आधार रहा है। यह नीति आर्थिक उन्नति और विदेशी धन को लुभाने का हथियार प्रतीत हो सकती है, पर यह असमानता की खाई को और गहरा रही है—जहां धनाढ्यों के लिए नागरिकता एक चमकता पुरस्कार बन गई है, वहीं मेहनतकश जन का अमेरिकी सपना कुहासे में और अधिक गुम हो गया है।

EB-5 वीज़ा, जो कभी 5 लाख डॉलर के निवेश पर टिका था, अब 50 लाख डॉलर की ऊंची छलांग लगा चुका है। यह परिवर्तन चीख-चीखकर घोषणा करता है कि अमेरिकी नीति अब परिश्रम और प्रतिभा को ताक पर रखकर धन-संपदा को सर्वोच्च आसन पर बिठा रही है। विदेशी पूंजी से अर्थव्यवस्था में उफान आएगा, रोजगार के नए द्वार खुलेंगे, और बाजार की नींव मजबूत होगी—यह सच है। मगर असली सवाल यह है कि इसकी मलाई कौन चखेगा? क्या यह योजना अमेरिकी नागरिकों और प्रवासियों के बीच असमानता की नई खाई नहीं खोद देगी? वे मेहनतकश लोग, जो वर्षों से कानूनी जंजालों में उलझे नागरिकता के सपने संजोए बैठे हैं, क्या अब खुद को और अधिक किनारे पर न पाएंगे?

यह योजना नागरिकता के मूलभूत आदर्शों को भी ललकार रही है। क्या नागरिकता अब महज एक कागजी सौदेबाजी बनकर रह जाएगी, या वह देश के साथ गहरे सांस्कृतिक और भावनात्मक रिश्ते की मूरत बनी रहेगी? अमेरिका का अब तक का पैगाम यही रहा है कि यहां कोई भी अपने खून-पसीने से शिखर छू सकता है। किंतु अब यह संदेश कुहासे में घुल रहा है—अगर तुम्हारे पास धन का ढेर है, तो स्वागत है; वरना दरवाजा बंद है। यह परिवर्तन न सिर्फ अमेरिका की चौहद्दी में असर डालेगा, बल्कि विश्व मंच पर भी गूंजेगा। यदि अमेरिका ने नागरिकता को पूंजी की कसौटी पर तौलना शुरू किया, तो अन्य देश भी इस राह के राही बन सकते हैं। इसका परिणाम होगा—दुनिया का निर्धन वर्ग अवसरों से और दूर छिटक जाएगा, और वैश्विक आर्थिक खाई और गहरी हो जाएगी।

ट्रंप का यह कदम उनके राजनीतिक एजेंडे से भी जुड़ा है। 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति, जो पहले आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन से जुड़ी थी, अब एक नए रूप में सामने आई है—जहां देश की पहचान को धन के तराजू में तौला जा रहा है। उनके समर्थक इसे साहसिक कदम कह सकते हैं, लेकिन आलोचकों का मानना है कि यह नीति प्रवासियों के लिए एक स्पष्ट नकारात्मक संकेत है। लाखों लोग, जो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर अमेरिकी नागरिक बनने का सपना देखते हैं, अब महसूस करेंगे कि उनके लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं।

यह नीति सामाजिक और राजनीतिक संग्राम को और भड़का सकती है। जब नागरिकता की बोली लगने लगेगी, तो क्या यह संदेश नहीं गूंजेगा कि राष्ट्र केवल धन कुबेरों का गढ़ है? क्या यह अमेरिका के मूल सिद्धांतों पर करारा प्रहार नहीं करेगा? यह नीति अमेरिका की वैश्विक छवि को भी धूमिल कर सकती है। अब तक अमेरिका को विविधता, समता और अवसरों की पावन भूमि माना जाता रहा है, किंतु यह परिवर्तन उसके प्राणतत्व को ही विकृत कर सकता है।

नागरिकता का मोल महज एक पासपोर्ट या कानूनी हक तक सीमित नहीं होता; यह तो एक व्यक्ति और राष्ट्र के बीच गहन बंधन व उसके समर्पण का प्रतीक है। ट्रंप की यह योजना उस पवित्र भाव को कुचल रही है, जिसने अमेरिका को महानता के शिखर पर पहुंचाया। यदि नागरिकता धन के बल पर हासिल होने लगे, तो मेहनतकश प्रवासियों के खून-पसीने से लिखे योगदान का क्या मोल रह जाएगा? क्या केवल धनाढ्य ही उस देश की आत्मा को थाम सकते हैं? शायद नहीं—यह सच कड़वा है, पर निर्विवाद है।

अमेरिका के इस साहसिक कदम का प्रभाव न केवल उसकी अर्थव्यवस्था की चहारदीवारी तक सीमित रहेगा, बल्कि यह विश्व भर में प्रवास, नागरिकता और अवसरों की अवधारणा को भी आमूल-चूल परिवर्तित कर सकता है। यह नीति अल्पकालिक आर्थिक उन्नति का झोंका तो ला सकती है, किंतु सामाजिक संतुलन और अमेरिका के मूलभूत आदर्शों पर इसका क्या प्रहार होगा, यह एक गहन चिंतन और विमर्श का प्रश्न है। यदि यह नीति विजयी हुई, तो अन्य राष्ट्र भी इस पथ पर कदमताल कर सकते हैं, परंतु यदि यह असफल रही, तो अमेरिका की वैश्विक प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगेगा।

यह परिवर्तन महज वर्तमान हालात का दर्पण नहीं, बल्कि एक व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति का संकेत है। अब यह देखने की बारी है कि क्या अमेरिका अपनी अस्मिता और मूल्यों की रक्षा कर पाएगा, या फिर पूर्णतः पूंजीवादी राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा—जहां नागरिकता भी एक व्यापारिक माल बनकर रह जाएगी।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

बोर्ड, यानी निगम, अंतिम निर्णय लिया गया ; प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा जल्द

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : राज्य भाजपा अध्यक्ष कौन होगा? बोर्ड और निगम में पद किसे मिलेंगे? मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा? इसको लेकर भाजपा खेमा काफी उत्तेजित है। कल दिल्ली से लौटने के बाद आज उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव के आवास पर भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल, मुख्यमंत्री मोहन माझी, राज्य प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ जैसे वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में विभिन्न बोर्डों एवं निगमों में नियुक्तियों के संबंध में विचार-मंथन सत्र आयोजित किया गया।जानकारी के अनुसार बोर्ड और निगम की जिम्मेदारी किस पर होगी? मैं पहले ही उच्च स्तरीय बैठक में भाग ले चुका हूं। इस संबंध में किसी भी समय घोषणा की जा सकती है। इस बीच, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।

पहली बार सत्ता में आने के बाद भाजपा पर्दे के पीछे संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे नेताओं को बोर्ड और निगमों में बहाल करने की योजना बना रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा अभी नहीं की गई है। मनमोहन सामल और गोलक महापात्रा इस दौड़ में आगे चल रहे हैं। निगम और बोर्ड की घोषणा के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है।

भाजपा और आप की नूराकुस्ती में जनता रही है पिस: डॉ. एमएल भास्कर

नई दिल्ली: जहांगीरपुरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष डॉ. एमएल भास्कर ने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी की नूराकुस्ती में दिल्ली की जनता फिर पिस रही है। उन्होंने आगे बताया कि दिल्ली में पिछले दस वर्षों से आम आदमी पार्टी का शासन रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के विकास पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण राजधानी दिल्ली की जनता को गंदे पानी, सड़को पर जलभराव, सीवर ओवरफ्लो सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और वायु प्रदूषण व दिल्ली में जाम की समस्या से भी लोग परेशान हुए।

श्री भास्कर ने कहा कि राजधानी दिल्ली की जनता ने विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा पर विश्वास किया है। जिस पर भाजपा को गंभीरता से सोचना होगा और दिल्ली की जनता को जो भी समस्याएं है, उनका समाधान करना होगा। उन्होंने कहा कि आप व भाजपा नूराकुस्ती न करें, बल्कि दिल्ली के विकास पर ध्यान दें, जिससे की जनता को सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि श्रीमती शीला दीक्षित के शासनकाल में दिल्ली में विकास ही विकास हुआ था, आज जो आप दिल्ली में फ्लाईओवर, बडे-बडे अस्पताल, मैट्रो रेल और लो-फ्लोर बसें देख रहे है, वह सब कांग्रेस पार्टी की देन है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत पहले की अपेक्षा काफी बढ़ा है और कई सीटों पर तो हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है।

राज्य का सर्वाधिक बड़ा औद्योगिक जिला में 172 रोजगार हेतु चयनित मधुसूदन विचार मंच ओड़िया रोजगार हेतु मुख्यमंत्री के साथ

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड

चाईबासा कमिश्नरी, झारखंड का सर्वाधिक उद्योग से भरा जिला सरायकेला खरसावां में वृहस्पतिवार को जिला नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेन्टर, सरायकेला-खरसावां के तत्वावधान में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। जहां 172 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जो हजारों भरे पड़े उद्योगों के दृष्टिकोण से काफी कम है। उधर सरकार का 75 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की निर्णय पर कोर्ट में एक मामला दायर होने के कारण आदेश अमल नहीं हुआ। कभी जिस सरायकेला के राजकुमार कुंवर विजय प्रताप सिंहदेव आदित्यपुर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के मुख्य अधिकारी होते थे तब टाटा कंपनी को भी सरायकेला राज्य के अनुबंध आधार पर स्थानीय लोगों को नौकरी देती पड़ती थी। परन्तु षड्यंत्र के तहत बिहार में सरायकेला भेजे जाने के बाद छपरा से आये टाटा कंपनी के अधिकारी आर एस पांडे ठीक उसका विपरित कार्य किया था। नतीजा तन 1958 से अपनी जमीन से उद्योग के लिए वे दखल किये गये स्थानीय लोगों अधिकार गंवाने पड रहे हैं, राची व दिल्ली में बैठे नेता अधिकारियों को इससे कुछ लेना दूं नहीं रह गया है।

नियोजन के संबंध में जिला नियोजन पदाधिकारी आलोक कुमार तोपनो ने बताया कि रोजगार मेला में रुंगटा माइन्स लिमिटेड, रामकृष्ण फोर्जिंगस लिमिटिड, बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज, रामकृष्ण कास्टिंग सोल्युशन लिमिटेड, बिग बास्केट-ए टाटा एंटरप्राइज, मित्तल मोटर्स, एलआईसी ऑफ़ इंडिया, युवा शक्ति फाउंडेशन, छवि कंस्ट्रक्शन, देलहीवेरी प्राइवेट लिमिटेड, फ्यूज़न फाइनेंस लिमिटेड, बीएन ट्रैक्टर्स एवं हरिओम कास्टिंग सहित कुल 18 संस्थानों के अधिकारियों द्वारा सेफ्टी सुपरवाइजर, ऑपरेटर, ईटीपी ऑपरेटर, एनपीडी इंजिनियर, मेंटेनेंस व डाई इंजिनियर, क्वालिटी हेड, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, सैप एग्जीक्यूटिव, डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट, सर्विस मैनेजर, मिग वेल्डर, सेंटर मैनेजर, क्वालिटी इंस्पेक्टर, सेल्स मैनेजर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर सहित विभिन्न पदों पर सरायकेला-खरसावां, चाईबासा एवं जमशेदपुर में नियुक्त करने हेतु 172 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया।

उन्होंने बताया कि जिला नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेन्टर, सरायकेला-खरसावां के सौजन्य से नियमित रूप से रोजगार शिविर एवं रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है। उन्होंने रोजगार की तलाश कर रहे जिले के सभी व्यक्तियों से आह्वान किया कि भविष्य में भी रोजगार मेला एवं भर्ती कैंप में अधिक से अधिक संख्या में भाग ले एवं रोजगार के अवसर प्राप्त करें। इसकी पूरी प्रक्रिया पूर्णता निशुल्क है।

हम बताते चलें कि कभी प्रख्यात संपादक, लेखक कालान्तर में सांसद बने स्वर्गीय सुरेंद्र मोहंती भी इसी सरायकेला में राजा व राजकुमार कुंवर विजय प्रताप सिंह देव के पास टाटा कंपनी से एक नौकरी पाने की आशा में आए थे। उन दिनों कुंवर विजय प्रताप महाराजा आदित्य प्रताप के नाम से प्रख्यात आदित्यपुर इलाका में राजकीय एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज के मुख्य थे। करण जब टाटा कंपनी का स्थापना 1890-1900 के इस पास हो रही थी तब धालभूम ओड़िया राजा से जमीन, मयूरभंज ओडिया राजा से गोरूमोहिषाणी लौह अयस्क एक रूपये रोयल्टी पर एशिया का प्रथम लौह अयस्क खान समेत सरायकेला राजा से मानव संसाधन (श्रमिक) लेने का वायदा किया था। ठीक आजादी के बाद ऐन केन प्रकारेण जब इलाका बिहार में गया तब सरायकेला, खरसावां, मयूरभंज, धालभूम राजाओं को तरहीज देने के बजाय टाटा ने बिहार सरकार को फायदा पहुंचाया। जो एक ऐतिहासिक शोषण कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहां आर एस पांडे जैसे अधिकारी को लाकर मुलवासी ओडिया भाषियों को उनका अधिकार देना बंद कर दिया। आज झारखंड सरकार स्थानीय को 75 प्रतिशत आरक्षण देने की प्रस्ताव पारित कर काम की है पर किन लोगों को यह लाभ मिल रहा है यह देखने वाली बात है। वैसे उपायुक्त सरायकेला, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम ने स्थानीय मूलवासी जन मानस के औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार गारंटी के लिए आज तक कुछ नहीं किया है यद्यपि इलाका ओडिया लोगों का रहा है। मधुसूदन विचार मंच अपनी उद्देश्य व ऐतिहासिक तथ्य के साथ मौजूदा झारखंड सरकार के पक्ष में 75 प्रतिशत मूल निवासी के खड़ा है, जहां कभी ओड़िया जनमानस का अधिकार रहा है, ।

रोजगार मेला में जिला नियोजन पदाधिकारी आलोक कुमार तोपनो, वाईपी रवि प्रकाश सिंह सहित जिला नियोजनालय के कर्मी सुरेंद्र रजक, सुजीत सरदार व अन्य एवं संबंधित संस्थानों के एचआर मैनेजर उपस्थित रहे।

आंखों से आंखें मिलाकर बात करना सीखें....

अच्छे कपड़े पहनें,छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं , ना कहना भी सीखें, व्यायाम करें ,ईश्वर में यकीन करें ,आंखों से आंखें मिलाकर बात करना सीखें,इसके अतिरिक्त भी आप अपना आत्म विश्वास बढ़ाने के लिए अपना आत्म-मूल्यांकन करें। यह आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकता है। आत्म-मूल्यांकन करने के लिए, आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं।

अपने बारे में लिखना शुरू करें।अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें।अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें।अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक योजना बनाएं। सकारात्मक सोच रखने से आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। नकारात्मक विचारों को दूर करें, अपने आप पर विश्वास रखें।अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए योजना बनाएं।

नई चीजें और कुछ नया सीखने से आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। नई चीजें सीखने से आप अपने कौशलों को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में खुद की मदद कर सकते हैं। नई चीजें सीखने के लिए,

ऑनलाइन कोर्सेज़ या ट्यूटोरियल्स का उपयोग करें।पुस्तकें पढ़ें या वीडियोज़ देखें।

अनुभवी लोगों से सीखें।अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, अपनी प्रगति को ट्रैक करें और आवश्यकतानुसार समायोजन करें।दूसरों की प्रशंसा करने से आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। दूसरों की प्रशंसा करने से आप अपने आप पर विश्वास रखने में मदद कर सकते हैं। दूसरों की प्रशंसा करने के लिए,दूसरों की अच्छाइयों को पहचानें।दूसरों के साथ सहानुभूति रखें। दूसरों की मदद करें।

अपनी ताकतों को पहचानें।अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें।अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें।

डॉ. मुश्ताक अहमद शाह
सहज हरदा मध्य प्रदेश

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023